https://www.facebook.com/KamalSandeshBjp/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'गरीबों, वंचितों के लिए काम करते रहेंगे'

वर्ष-12, अंक-08, 16-31 अप्रैल, 2017 (पाक्षिक) ₹20

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस' के नए युग की शुरुआत

संसद ने पारित किया ऐतिहासिक 'जीएसटी' विधेयक

'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' बनाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं: रामलाल

उप्र: किसानों के 36,000 करोड़ रुपये के फसली ऋण माफ

भाजपा के 37वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **'हमने परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को खत्म करके 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉरमेंस' के नए युग की शुरुआत की है'**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 29 मार्च को अहमदाबाद (गुजरात) में आयोजित विशाल विजय विश्वास कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से आसन्न गुजरात विधान...

वैचारिकी

लौकिक, धर्महीन, धर्मरहित, धर्मनिरपेक्ष, अधार्मिक, अधर्मी,... 12

श्रद्धांजलि

सुन्दर सिंह भण्डारी: शत शत नमन! 14

विशेष साक्षात्कार

'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' बनाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं: रामलाल 15

लेख

कृषि और अम्बेडकर के सपनों का भारत 22

भारत ने ई-वीज़ा शक्ति का विस्तार किया 23

नए वित्तीय वर्ष 2017 में जीएसटी की प्रभावी शुरुआत 24

अन्य

14,933 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई 10

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को मंजूरी 17

पूरे देश में एक जैसी टैक्स प्रणाली होगी: अरुण जेटली 19

प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में चेनानी-नाशरी सुरंग राष्ट्र को समर्पित की 21

दीन दयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 30

किसानों के 36,000 करोड़ रुपये के फसली ऋण माफ 32

101 नई एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी 33

संगठनात्मक गतिविधियां

08 **गरीबों, वंचितों के लिए काम करते रहेंगे: नरेन्द्र मोदी**

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को भाजपा के 37वें स्थापना दिवस पर पार्टी...

26 **देश के सभी वर्गों ने पार्टी में विश्वास जताया: नरेंद्र मोदी**

6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल...

सरकार की उपलब्धियां

09 **संसद ने पारित किया ऐतिहासिक 'जीएसटी' विधेयक**

राज्य सभा द्वारा 6 अप्रैल को ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित...

11 **पहली बार विद्युत का निवल निर्यातक बना भारत**

बिजली के सीमा पार व्यापार के लिए भारत सरकार के निर्दिष्ट प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@nitin_gadkari

प्रत्येक भारतीय के लिए ब्रह्मपुत्र ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्र समारोह में उपस्थित होकर गौरव महसूस होता है।

@rsprasad

जनधन, आधार और मोबाइल (जेएएम ट्रीनिटी) से लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई।

@MVenkaiahNaidu

सरकार द्वारा 'कौशल विकास' के विशाल कार्यक्रम की शुरुआत से बीवाईएसटी जैसे संगठन परामर्श के माध्यमों से उन्हें उपयोगी मदद कर सकते हैं।

@dasraghubar

शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार से ही समाज को जागरूक बनाया जा सकता है। बेटा-बेटी में भेद न करें। बच्चियों की शादी बालिग होने पर ही करें।

facebook

GST बिल पास होने पर सभी देशवासियों को बधाई! नया साल, नया कानून, नया भारत!

-नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मात्र 11 माह में 2 करोड़ से अधिक परिवारों को गैस सिलिंडर देकर उनके जीवन से धुआं दूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं श्री धर्मेन्द्र प्रधान का हार्दिक अभिनंदन। 2 करोड़ परिवारों को मिली यह अभूतपूर्व सेवा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जनकल्याण संकल्प और श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी के लगन का परिणाम है।

-अमित शाह

चंपारण सत्याग्रह के सौ वर्ष पूरे होने पर बापू के स्वच्छ भारत के निर्माण के सपनो को पूरा करने के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता के लिए उन्हें बधाई। स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प प्रेरणा देता है।

-भूपेन्द्र यादव

व्यंग्य चित्र

'कमल संदेश' की ओर से सुधी पाठकों को

अक्षय तृतीया

की हार्दिक शुभकामनाएं!

पाथेय

हमारे अधिकांश राजनीतिक टीकाकार भारत के सामाजिक मुद्दों को या तो हिंदू-मुस्लिम प्रिज्म के माध्यम से देखते हैं अथवा वर्ग तथा जाति के कठोर ढांचे में रखकर देखते हैं और ऐसा करते समय वे न केवल अन्य सामाजिक विशेषताओं को नजरअंदाज कर देते हैं, अपितु इन विविधताओं में अंतर्निहित एकत्व और सामंजस्य को भी नहीं देख पाते। यदि असलियत इतनी सरल होती जैसा कि राजनीतिक एवं मीडिया क्षेत्रों में कल्पना की जा रही है, तो हमारी समस्याएं बहुत पहले सुलझा ली गई होती। विविधता शक्ति का स्रोत है, किंतु शक्ति तभी प्राप्त होती है, यदि उसमे निहित एकता को पहचान लिया जाये, सुरक्षित रखा जाये और बढ़ाया जाये।

-कुशाभाऊ ठाकरे

'अंधेरा छंटा और कमल खिला...'

अपने 37वें स्थापना दिवस मनाते समय भाजपा जिन ऊंचाइयों को छू रही है वह अभी कुछ वर्षों पहले तक कई लोगों को असंभव सा प्रतीत होता था। वर्षों तक पार्टी के लिए अथक पसीना बहाने वालों के लिए यह यात्रा केवल शुरुआत भर है, जिसका उन्होंने स्वप्न देखा था। 'जनता पार्टी' के प्रयोग के असफल होने के कटु अनुभव से सीख लेकर 6 अप्रैल 1980 को नए उत्साह एवं संकल्प के साथ भाजपा का गठन हुआ। चुनौती को स्वीकार करते हुए अटलजी ने कहा था, 'अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा'। उस समय किसने सोचा होगा कि मात्र दशक भर में यह संकल्प यथार्थ में परिणत हो जाएगा। नेतृत्व के इस आत्मविश्वास के पीछे की शक्ति उन हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं से निकलती है, जिनका पार्टी विचारधारा पर अटूट विश्वास रहा है। जनसंघ की विरासत को अपने कंधों पर संभाले भाजपा ने कांग्रेस के एक-दलीय वर्चस्व को न केवल चुनावी मैदान में तोड़ा, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने अथाह समर्पण से इसे विचारधारा की चुनौती भी दी। जहां भाजपा देश को एक गौरवशाली भविष्य की ओर ले जाने को तत्पर है, वहीं विपक्ष लगातार हार पर हार झेलने को मजबूर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय राजनीति की धारा को भाजपा के कर्मठ एवं समर्पित कार्यकर्ताओं ने मोड़ दिया है। वैचारिक प्रतिबद्धता एवं राष्ट्र के प्रति निःस्वार्थ सेवा की भावना ही भाजपा कार्यकर्ताओं की पहचान बन गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में देश नए जोश एवं उत्साह से तीव्र विकास की राह में बढ़ चुका है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अनुसार यह महान भारत बनाने के सपनों के प्रति समर्पण का प्रतिफल है, जिसने नेतृत्व एवं कार्यकर्ताओं को विचारधारा के प्रति निष्ठा, अटूट संकल्प के साथ कड़े परिश्रम के लिए प्रेरित किया। एकात्म मानव दर्शन एवं अंत्योदय पार्टी के पथ प्रदर्शक सिद्धांत रहे हैं। इन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा तथा सरकार की गांव, गरीब एवं किसान समर्थक नीतियों में देखा जा सकता है। युवा एवं महिला संबंधी कार्यक्रमों से समाज में एक नई ऊर्जा आयी है। क्या भारत बिना गरीब, वंचित एवं शोषितों का कल्याण किए आगे बढ़ सकता है? क्या भारत, गांव जहां हमारे देश की बहुसंख्य जनता रहती है, के विकास के बिना विकसित हो सकता है? क्या भारत, महिलाओं- जो देश की आधी आबादी है, के सशक्तिकरण के बिना प्रगति कर सकता है? युवाओं में ऊर्जा भरे बिना क्या भारत का भविष्य हो सकता है? क्या भारत, भारत हो सकता है यदि इसे अपनी ज्ञान, परंपराओं एवं बौद्धिक क्षमता पर विश्वास न हो? क्या भारत मानवता की प्रगति में योगदान दे सकता है यदि यह स्वयं विकसित एवं सुशासित न हो? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मोदी सरकार अभिनव योजनाओं एवं कार्यक्रमों से दे रही है तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन से भारत की तस्वीर बदल रही है। अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों में पुनः जीवन के बीज अंकुरित हो रहे हैं तथा प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत देखरेख में जीवन का स्पंदन महसूस कर रहे हैं। निर्णायक सरकार द्वारा उठाये गए ठोस कदमों से पूरा देश व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।

आज जब भारत अपनी चिरनिद्रा से उठ रहा है और 'मां भारती' विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होने को तत्पर है, विश्व कल्याण के उद्घोष के साथ मानवता को विभाजनकारी विचारों से मुक्त कराने का वृहत् दायित्व का भान सभी को हो रहा है। भाजपा स्थापना दिवस पर हर कार्यकर्ता को उन उच्च लक्ष्यों के प्रति सजग हो राष्ट्रवाद, विकास एवं सुशासन के प्रति कृत-संकल्पित होना पड़ेगा।

भारत न केवल आदिकाल से चला आ रहा एक जीवंत सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, वरन एक ऐसा महान राष्ट्र है जिसका एक गौरवशाली इतिहास है। इसकी हजारों वर्ष की यात्रा विदेशी आक्रमणों, शासन एवं औपनिवेशिक सत्ता से बाधित होती रही, लेकिन इन अनगिनत आक्रमणों का प्रतिकार कर भारत न केवल पुनः खड़ा हुआ बल्कि आक्रांताओं की वैचारिक चुनौतियों को भी स्वीकार किया।

स्वतंत्रता के पश्चात् अपेक्षा यह थी कि भारत एवं भारतीयता और अधिक प्रखर होगी, पर कांग्रेस नेतृत्व इस जनाकांक्षा को समझने में असफल रही। भारतीय राष्ट्रीयता के प्राचीन आधार तथा आदिकाल से वर्तमान की निरंतरता को निरंतर अस्वीकार करने के कारण कांग्रेस की आज यह गति हुई है। कांग्रेस के लगातार नकारात्मक रुख के कारण देश की जनता ने अब यह दायित्व भाजपा के कंधों पर ने डाल दिया है और स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में भारत को अपनी नियति तक ले जाने की जिम्मेदारी अब भाजपा पर है। आज जब भारत अपनी चिरनिद्रा से उठ रहा है और 'मां भारती' विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होने को तत्पर है, विश्व कल्याण के उद्घोष के साथ मानवता को विभाजनकारी विचारों से मुक्त कराने का वृहत् दायित्व का भान सभी को हो रहा है। भाजपा स्थापना दिवस पर हर कार्यकर्ता को उन उच्च लक्ष्यों के प्रति सजग हो राष्ट्रवाद, विकास एवं सुशासन के प्रति कृत-संकल्पित होना पड़ेगा। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

'हमने परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को खत्म करके 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉरमेंस' के नए युग की शुरुआत की है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 29 मार्च को अहमदाबाद (गुजरात) में आयोजित विशाल विजय विश्वास कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से आसन्न गुजरात विधान सभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा कर मोदी जी के विजय रथ को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत हमारा संगठन और हमारे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के कारण ही आज कच्छ से लेकर कामरूप तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण ही 1995 से लेकर अब तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि की शुरुआत में कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन आयोजित किया गया है, गुजरात में एक बार फिर से भाजपा का परचम लहराने की दिशा में यह पहला कदम है। उन्होंने कहा कि मैंने भी अपनी राजनीति की शुरुआत एक छोटे से बूथ कार्यकर्ता के रूप में की थी। उन्होंने कहा कि एक समय संसद में हमारे दो ही प्रतिनिधि हुआ करते थे, तो राजीव गांधी जी ने ताना मारा था कि भारतीय जनता पार्टी हम दो, हमारे दो में विश्वास रखती है लेकिन देखिये, आज कांग्रेस 44 पर सिमट कर रह गई है। उन्होंने कहा कि 10 सदस्यों से बनी पार्टी आज देश ही नहीं, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आज देश में भाजपा के लगभग 1300 से अधिक विधायक हैं, 300 से अधिक सांसद हैं और 15 राज्यों में भाजपा एवं एनडीए की सरकारें हैं।

श्री शाह ने कहा कि आज मैं आप सबको प्रणाम करने आया हूं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता है। उन्होंने कहा कि यहीं साबरमती नदी के किनारे स्वतंत्र भारत की नींव रखी गई थी, आज हम फिर से यहां 150 सीटें जीतने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसका सीधा गणित समझाना चाहता हूं, श्री नरेन्द्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी ने 126 सीटें जीती थीं, अब तो वे प्रधानमंत्री हैं तो निश्चित ही भाजपा गुजरात में 150 सीटें जीतेगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया था कि केंद्र की उनकी सरकार गरीबों, दलितों और निर्बलों की सरकार होगी और लगभग तीन साल के कार्यकाल में

प्रधानमंत्री जी ने इसे चरितार्थ करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने कहा कि विकास के गुजरात मॉडल के कारण देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सराहना होती है, इसका श्रेय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को जाता है।

कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को यह पता होना चाहिए कि 1990 के बाद भारतीय जनता पार्टी गुजरात में विधानसभा का एक भी चुनाव हारी नहीं है। उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस हर बार कहती है कि 'आवे छे, आवे छे, आवे छे' लेकिन हर बार गुजरात की जनता ने यह सिद्ध करके दिखाया है कि कांग्रेस 'जावे छे, जावे छे, जावे छे।' उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस का 'आवे छे' का जो सपना था, वह पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद चकनाचूर हो गया है। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों के चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत कोई जातिवाद अथवा परिवारवाद के आधार पर नहीं, बल्कि विकास कार्यों के आधार पर हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को ख़त्म करके पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस के एक नए युग की शुरुआत की है।

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनने से पहले की स्थिति पर चर्चा करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 1995 से पहले एक साल में 200 दिन तक कर्फ्यू लगा रहता था, लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, जातिवाद का जहर फैला कर समाज को बांटने की राजनीति हो रही थी, यहां बेग़म-बादशाह का राज चलता था। उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गुजरात हर क्षेत्र में विकास के नए मापदंड स्थापित कर रहा है और विश्व भर में विकास के गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने गुजरात के विकास के लिए कई काम किये हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय गुजरात को जहां विकास के लिए केवल 43 हजार करोड़ मिलते थे, वहीं मोदी सरकार में यह राशि बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपये हो गई है जिससे राज्य में विकास कार्यों में और अधिक तेजी आई है।

श्री शाह ने कहा कि गुजरात के चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आयेंगे, कांग्रेस की ओर से झूठे और तथ्यहीन आरोप लगते रहेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष जितने आरोप लगाएगा, कमल उतना ही और खिलेगा। आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव आते ही दिखती है और चुनाव जाते ही अदृश्य हो जाती है।

भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार में क्या बदल गया, पहले भी सीमा पर गोलीबारी होती थी, आज भी सीमा पर गोलीबारी होती है। उन्होंने कहा कि राहुल जी, आपको यह समझ में नहीं आयेगा, आपकी आंखों पर इटैलियन चश्मा जो लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले जब सीमा पर गोलीबारी होती थी तो उसकी शुरुआत भी पाकिस्तान की सेना करती थी और अंत भी पाकिस्तान की सेना ही करती थी, लेकिन आज जब कभी सीमा पर गोलीबारी होती है तो आज भी उसकी शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना ही करती है लेकिन उसका अंत हिन्दुस्तान की सेना करती है। उन्होंने कहा कि उरी में जब पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों के कायराना हमले में हमारे जवान शहीद हुए तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और हमारे बहादुर जवानों के पराक्रम के बल पर पाकिस्तान की जमीन में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके जवानों की शहादत का बदला लिया गया, इसे कहते हैं बदलाव राहुल जी।

> गुजरात में कांग्रेस हर बार कहती है कि 'आवे छे, आवे छे, आवे छे' लेकिन हर बार गुजरात की जनता ने यह सिद्ध करके दिखाया है कि कांग्रेस 'जावे छे, जावे छे, जावे छे।'

कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में संगठित होकर लड़े, हमें 150 सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अगुआई में संकल्प करते हैं कि हम गुजरात में एक और प्रचंड विजय की ओर आगे बढ़ेंगे और मोदी जी के विजय रथ को आगे बढायेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं तो सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा, हां, हम तैयार हैं। ■

गरीबों, वंचितों के लिए काम करते रहेंगे: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को भाजपा के 37वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष को याद किया और कहा कि अंत्योदय के मंत्र के साथ पार्टी भारत, खासकर गरीबों एवं वंचितों की सेवा करने के अपने प्रयासों को पूरे जोश से आगे बढ़ाते रहेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय गए। श्री मोदी और श्री शाह ने भाजपा के विचारक पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री मोदी ने ट्वीट किया, "भाजपा के स्थापना दिवस पर मैं भाजपा कार्यकर्ताओं के पूरे परिवार को बधाई देता हूं जो पूरे भारत में काम कर रहे हैं।"

श्री मोदी ने कहा कि हम भाजपा कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों की कड़ी मेहनत को गौरव के साथ याद करते हैं जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी कोशिशों से एक एक ईट जोड़कर पार्टी को खड़ा किया।

श्री मोदी ने पं. दीनदयाल उपाध्याय को प्रेरणा का स्रोत बताया।

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि यह गौरव की बात है कि सम्पूर्ण भारत और समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया है। मोदी ने सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

श्री मोदी ने कहा कि अंत्योदय के मंत्र का पालन करते हुए हम भारत, खासकर गरीबों एवं वंचितों की सेवा करने के अपने प्रयासों को पूरे जोश से आगे बढ़ाते रहेंगे।

गौरतलब है कि भाजपा की स्थापना छह अप्रैल 1980 को हुई थी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने ट्वीट किया, "37 वर्षों से राष्ट्र सेवा को समर्पित भाजपा के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं।"

श्री शाह ने कहा कि विचारधारा आधारित एक छोटे से पौधे को अपने अमूल्य एवं कठोर परिश्रम से विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को नमन।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन एवं विकास नीति में निरंतर विश्वास प्रकट करने के लिए देश की जनता का हृदय से अभिनंदन करती है। ■

संसद ने पारित किया ऐतिहासिक 'जीएसटी' विधेयक

राज्य सभा द्वारा 6 अप्रैल को ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित होते ही देश में एक नई सरल कर-प्रणाली का अध्याय शुरू हो गया। सच तो यह है कि जीएसटी आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार है। यह सरल कर प्रक्रिया को लागू करने पर जोर देता है और इस कर के ऊपर कोई कर नहीं लगता। जीएसटी राज्यों के बीच वस्तुओं की आवाजाही में मदद करता है और राजस्व में बढ़ोत्तरी के साथ साथ कर चोरी पर लगाम लगाता है। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार में आसानी होगी और लालफीताशाही में कमी आएगी।

राज्य सभा ने 6 अप्रैल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक से जुड़े चारों बिलों को मंजूरी दे दी। जीएसटी से जुड़े चार विधेयक हैं-केंद्रीय माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 (सी-जीएसटी बिल), एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आई-जीएसटी बिल), संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूटी-जीएसटी बिल) और माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक 2017। गौरतलब है कि जीएसटी को लोकसभा को पहले ही (29 मार्च) पारित कर चुकी है। जीएसटी से जुड़े विधेयकों को पारित होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई दी। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा बताया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने भी नए टैक्स सिस्टम को ऐतिहासिक करार दिया। नयी कर प्रणाली में उपभोक्ताओं और राज्यों के हितों को सुरक्षित रखा जायेगा। कृषि पर कर नहीं लगेगा। जिन खाद्य वस्तुओं पर फिलहाल शून्य कर है, जीएसटी में भी कर नहीं लगेगा।

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था में 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें तय की गयी हैं। लक्जरी कारों, बोतल बंद सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू उत्पाद जैसी अहितकर वस्तुओं एवं कोयला जैसी पर्यावरण से जुड़ी सामग्री पर इसके ऊपर सेस भी लगाने की बात है। 28 प्रतिशत से अधिक लगने वाला सेस मुआवजा कोष में जायेगा और जिन राज्यों को नुकसान हो रहा है, उन्हें इसमें से राशि दी जायेगी।

लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद सभी अन्य कर हटा दिए जाएंगे और इसके बाद सामान थोड़े सस्ते हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी अन्य कर जैसे राज्यों में प्रवेश कर को जीएसटी को लागू करने के बाद हटा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "एक बार जब सभी किस्म के करों को हटा दिया जाएगा तो वस्तुएं थोड़ी सस्ती हो जाएंगी।" श्री जेटली ने कहा, "भारत आर्थिक रूप से अभी भी अलग-अलग इकाई बना हुआ है। राज्यों की सीमाओं पर कर चुकाने के इंतजार में ट्रकों की बड़ी-बड़ी लाइनें लगी होती हैं। यहां सामानों की मुक्त आवाजाही नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य पदार्थों पर कोई कर नहीं वसूला जाएगा।

उन्होंने कहा, "परिषद ने पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल करने का फैसला इसे लागू करने के एक साल बाद करेगी। फिलहाल सांविधानिक रूप से पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के अंतर्गत हैं, लेकिन उन पर कर की दर शून्य रखी गई है। इसलिए जब परिषद इस पर जीएसटी के तहत कर लगाने का फैसला करती है, तो हमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी।"

जीएसटी से जुड़े चार विधेयक हैं-केंद्रीय माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 (सी-जीएसटी बिल), एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आई-जीएसटी बिल), संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूटी-जीएसटी बिल) और माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक 2017।

श्री जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद पहली संघीय निर्णय करने वाली संस्था है। संविधान संशोधन के आधार पर जीएसटी परिषद को मॉडल कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जहां तक कानून बनाने की बात है तो यह संघीय ढांचे के आधार पर होगा, वहीं संसद और राज्य विधान सभाओं की सर्वोच्चता बनी रहेगी। हालांकि इन सिफारिशों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अलग अलग राज्य अगर अलग दर तय करेंगे तो अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यह इसकी सौहार्दपूर्ण व्याख्या है और इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। ■

1.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का पता चला

14,933 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने पिछले तीन वर्षों में काला धन समाप्त करने में अपार सफलता प्राप्त की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 7 अप्रैल को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों में 1.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का पता लगाया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में अप्रत्याशित कानूनी कार्रवाई की गई। जहां 23064 सर्च/सर्वे किए गए (आयकर 17525, सीमा शुल्क 2509, केंद्रीय उत्पाद 1913, सेवा कर 1120), वहीं 2814 मामलों में आपराधिक मुकदमे किए गए (आयकर 1966, सीमा शुल्क 526, केंद्रीय उत्पाद 293, सेवा कर 29)। 3893 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया (सीमा शुल्क 3782, केंद्रीय उत्पाद 47, सेवा कर 64)।

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन (मनी लॉड्रिंग) विरोधी कारर्वाइयों में तेजी दिखाते हुए 519 मामले दर्ज किए और 396 सर्च आपरेशन किया गया। 79 मामलों में गिरफ्तारियां की गईं और 14,933 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। बेनामी प्रतिषेध कानून पिछले 28 वर्षों तक निष्प्रभावी रहा । इसे नवंबर 2016 से व्यापक संशोधन करके प्रभावी बनाया गया है। 245 से अधिक बेनामी लेनदेन का पता लगाया गया। 124 मामलों में 55 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति अस्थाई रूप से जब्त की गई है।

विभिन्न कानूनों को तर्कसंगत बनाया गया, कमियों को दूर किया गया और दण्डात्मक प्रावधानों को कठोर बनाया गया। विभिन्न तरीकों से नकद लेनदेन पर नजर रखने और नकद लेनदेन पर नियंत्रण रखने के प्रयास किए गए हैं। ऐसे तरीकों में 2 लाख रुपये से ऊपर के नकदी लेनदेन में दंड का प्रावधान, अनुमति योग्य नकद खर्च की सीमा केवल 10,000 रुपये रखना, पैन संख्या प्राप्त करने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की अनिवार्यता तथा 50,000 रुपये से अधिक की नकदी जमा के लिए पैन की अनिवार्यता, बैंक खातों से आधार को आवश्यक रूप में जोड़ना, अचल संपत्ति के हस्तांतरण मामले में 20,000 रुपये और उससे अधिक की रकम पर दण्ड और यह दण्ड बराबर की राशि होगा। ■

'1.25 करोड़ लोग 'भीम' ऐप से जुड़े'

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि कैशलेस लेने-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में नकदरहित लेन-देन के लिए शिक्षित युवाओं की बढ़ती संख्या देखते हुए पहली बार सरकार ने एक सरल भीम ऐप लांच किया है जो कि अत्यधिक लोकप्रिय है। अब तक 1.25 करोड़ लोग इस भीम ऐप से जुड़ चुके हैं और इसकी मदद से कुल 361 करोड़ रूपये का लेन-देन किया जा चुका है।

कृषि मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नये भारत यानी न्यू इंडिया का आह्वान किया है जिसमें कालेधन और भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। देश में डिजिधन और कैशलेस लेनदेन को आगे ले जाना भी प्रधानमंत्री की इसी सोच का हिस्सा है। श्री सिंह ने यह बात 27 मार्च को मोतिहारी के में आयोजित डिजिधन मेले के उद्घाटन के अवसर पर कही।

श्री सिंह ने कहा कि देश में 100 करोड़ से ज्यादा फोन हैं जिसमें से 30-40 करोड़ स्मार्ट फोन हैं एवं करीब 50 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता हैं। अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि यूपीआई कार्ड बैंकों द्वारा बनाई नई व्यवस्था है, जिसमें मोबाईल एप्प डाउनलोड करने के बाद किसी भी बैंक से फोन नम्बर के आधार पर लेन-देन किया जा सकता है।

श्री सिंह ने बताया कि रेल विभाग में कुल 2.15 करोड़ रेलवे टिकट बुक होते हैं, जिसमें से 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं। श्री सिंह ने जानकारी दी कि कुल बैंक अकाउंट 144 करोड़ हैं जिसमें से 117 करोड़ सेविंग्स अकाउंट हैं। कुल जन-धन अकाउंट 28.02 करोड़ हैं। 40 करोड़ बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जुड़े हैं। कुल आधार कार्ड की संख्या है 113 करोड़।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि कुल POS मशीन की संख्या है 20.13 लाख एवं मार्च, 2017 तक इसमें 10 लाख नई मशीनें जोड़ी जायेंगी। इसके अलावा देश में करीब 5.7 करोड़ E-Wallet Users हैं। देशभर में कुल 110.6 करोड़ क्रेडिट/डेबिट कार्ड हैं। 21.9 करोड़ लोगों के पास रूपे कार्ड हैं जिसका इस्तेमाल वर्तमान में 40 प्रतिशत बढ़ा है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय कृषि से जुड़े हर लेनदेन में कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है और इसके लिए हर सुविधा मुहैया करवा रहा है। ■

पहली बार विद्युत का निवल निर्यातक बना भारत

बिजली के सीमा पार व्यापार के लिए भारत सरकार के निर्दिष्ट प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत पहली बार बिजली के निवल आयातक की बजाए निवल निर्यातक बना। वर्ष 2016-17 (अप्रैल से फरवरी 2017) के दौरान भारत ने नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को 579.8 करोड़ यूनिट बिजली निर्यात की, जो भूटान से आयात की जाने वाली करीब 558.5 करोड़ यूनिटों की तुलना में 21.3 करोड़ यूनिट अधिक है।

पिछली सदी में सीमा पार विद्युत व्यापार प्रारंभ होने के बाद से भारत, भूटान से विद्युत आयात करता रहा है और बिहार और उत्तर प्रदेश से 33 केवी और 132 केवी रेडियल मोड में नेपाल को मामूली विद्युत का निर्यात करता रहा है। भूटान औसत रूप में भारत को 500-550 करोड़ यूनिट विद्युत की आपूर्ति करता रहा है।

भारत नेपाल को 11 केवी, 33 केवी और 132 केवी लेवल पर 12000 से अधिक सीमा पार इंटर कनेक्शनों के लिए करीब 190 मेगावाट विद्युत का निर्यात भी करता रहा है। 2016 में 400 केवी लाइन क्षमता (132 केवी क्षमता के साथ संचालित) मुजफ्फरपुर (भारत)-धालखेबर (नेपाल) के चालू हो जाने के बाद नेपाल को विद्युत निर्यात में करीब 145 मेगावाट का इज़ाफा हुआ।

भारत से बांग्लादेश को किए जाने वाले विद्युत निर्यात में उस समय वृद्धि हुई, जब सितम्बर, 2013 में 400 केवी क्षमता का पहला सीमा पार इंटर-कनेक्शन चालू हुआ। इसी तरह भारत में

सुर्जामणिनगर (त्रिपुरा) और बांग्लादेश में दक्षिण कोम्मिल्ला के बीच दूसरा सीमा पार इंटर-कनेक्शन चालू होने के बाद भारत के निर्यात में और बढ़ोत्तरी हुई।

132 केवी काटिया (बिहार)–कुसाहा (नेपाल) और 132 केवी रक्सौल (बिहार)–पार्वाणीपुर (नेपाल) सीमा पार इंटर-कनेक्शन चालू हो जाने के बाद नेपाल को किए जाने वाले विद्युत निर्यात में करीब 145 मेगावाट की वृद्धि होने का अनुमान है। ■

पिछले वित्तीय वर्ष में पवन ऊर्जा में 5400 मेगा वाट की रिकार्ड वृद्धि

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वर्ष 2016-17 में 5400 मेगा वाट की वृद्धि कर एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 206-17 के दौरान 4000 मेगावाट वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस वर्ष पिछले साल हुई 3423 मेगावाट की वृद्धि को पार कर लिया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान पवन ऊर्जा में वृद्धि में आंध्र प्रदेश का 2190 मेगावाट, इसके बाद गुजरात का 1275 मेगावाट और कर्नाटक का 882 मेगावाट का योगदान रहा। इसके साथ ही वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलांगना और केरल का योगदान क्रमशः 357 मेगावाट, 288 मेगावाट, 262 मेगावाट, 118 मेगावाट, 23 मेगावाट और 8 मेगावाट का रहा।

वर्ष 2016-17 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बोली लगाने की शुरूआत सहित रिपावरिंग नीति, पवन-सौर संकर नीति का मसौदा बनाने, नई पवन ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए दिशा निर्देश की नीतिगत पहल की गई। ■

लौकिक, धर्महीन, धर्मरहित, धर्मनिरपेक्ष, अधार्मिक, अधर्मी, निधर्मी अथवा असांप्रदायिक

| दीनदयाल उपाध्याय |

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारतवर्ष को एक 'सेक्यूलर स्टेट' घोषित किया गया है तथा तबसे यह शब्द लोगों की जबान पर इतना चढ़ गया है कि क्या बड़े-बड़े नेता और क्या गांव-गांव, गली-गली में बातचीत के स्वर को ऊँचा करके ही भाषण की हवस मिटाने वाले छुटभैये, सभी दिन में चार बार 'सेक्यूलर स्टेट' की दुहाई देकर अपनी बात मनवाने का तथा दूसरों को उसके विरुद्ध बताकर गलत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। सुनते-सुनते शब्द तो कानों में रम गया है, किंतु अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भारत सरकार बोलने वाले नेता तथा सुनने वाली जनता 'सेक्यूलर' शब्द का क्या अर्थ समझती है। विधान परिषद् में 'सेक्यूलर स्टेट' का नाम लेने पर जब एक सदस्य ने पं. जवाहरलाल नेहरू से 'सेक्यूलर स्टेट' का मतलब पूछा तो उन्होंने भी अर्थ बताने के स्थान पर सम्मानीय सदस्य को डांटकर कोष देखने के लिए कहा। फलतः समस्या सुलझ नहीं पाई और आज भी लोग सेक्यूलर शब्द से भिन्न-भिन्न अर्थ लगाते हैं। सेक्यूलर के लिए भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त पर्यायों से यह भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। लौकिक, धर्महीन, धर्मरहित, धर्मनिरपेक्ष, अधार्मिक, अधर्मी, निधर्मी, असांप्रदायिक आदि अनेक शब्दों का सेक्यूलर के पर्याय इस नाते प्रयोग होता है। निश्चित ही उपर्युक्त सभी शब्द समानार्थक नहीं हैं। उनमें मत भिन्नता ही नहीं है अपितु वे विरोध की सीमारेखा को भी स्पर्श कर जाते हैं। अपने राज्य के स्वरूप के संबंध में इतना वैषम्य वास्तव में हितावह नहीं है। अच्छा हो कि हम सेक्यूलर शब्द के ठीक अर्थ समझ लें; कम-से-कम जिस अर्थ में हम भारत को सेक्यूलर स्टेट बनाना चाहते हैं, उसका तो निर्णय कर ही लेना चाहिए।

रोमन साम्राज्य को प्रतिक्रिया

नेहरूजी के आदेशानुसार यदि डिक्शनरी का सहारा लिया जाए तो समस्या विशेष नहीं सुलझती, क्योंकि कोष में सेक्यूलर के अर्थ हैं अर्थात् अपना सौ वर्षों में एक बार होने वाला लौकिक। इनमें से लौकिक अर्थ सर्वसाधारण व्यवहार में आता है तथा स्प्रिचुअल के विरोध में इसका प्रयोग होता है। सेक्यूलर स्टेट को कल्पना के विकास के पीछे भी यही भाव है। क्योंकि सेक्यूलर स्टेट की कल्पना का उदय पवित्र रोमन साम्राज्य के विरोध में से हुआ है। यूरोप के सभी देश किसी समय रोम के पोप के अधीन थे तथा प्रत्येक देश का राजा पोप के नाम पर ही शासन करता था। किंतु धीरे-धीरे रोमन कैथोलिक मत और पोप दोनों या इनमें से किसी एक के प्रति अविश्वास और विरोध की भावना बढ़ने लगी। फलतः प्रोटेस्टेंट मत का जन्म हुआ तथा फ्रांस की क्रांति के कारण और उसके परिणामस्वरूप जनता के घोष समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व हुए। साथ ही राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ईसाई मत में अनेक चर्चों की स्थापना ईसाई मत के सामान्य जीवन पर घटते हुए प्रभाव ने पवित्र रोमन साम्राज्य को विघटित करके, ऐसे राज्य की कल्पना को जन्म दिया जिसमें सभी मतों के मानने वाले नागरिकता के समान अधिकारों का उपयोग कर सकें तथा राज्य जनता के मत में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। लोगों की दृष्टि अधिकाधिक भौतिकवादी होने के कारण लोगों की दृष्टि में राज्य का महत्त्व केवल लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र रह गया है तथा आत्मा संबंधी सभी प्रश्नों की व्यक्तिगत इच्छा-अनिच्छा पर छोड़ देना उचित समझा।

लौकिक और पारलौकिक

यूरोप में 'सेक्यूलर स्टेट' की कल्पना के विकास का संक्षिप्त विवरण ऊपर दिया है। स्प्रिचुअल और टेंपोरल (सेक्यूलर) दो भिन्न-भिन्न क्षेत्र करके राज्य की ओर केवल सेक्यूलर आवश्यकताओं की पूर्ति का भार देकर भी यूरोप का कोई राज्य मत विशेष के पक्षपात की नीति से मुक्त नहीं हो पाया है। इंग्लैंड का राजा अभी भी (धर्मरक्षक) कहा जाता है तथा उसके लिए आवश्यक है कि वह मानने वाला प्रोटेस्टेंट ही हो, राज्य की ओर से गिरजे और पादरियों को पतन और सहायता भी मिलती है। अमेरिका में भी प्रेसीडेंट के लिए शपथ लेते समय विशिष्ट धार्मिक विधि को पूरा करना आवश्यक है।

भारतवर्ष में वास्तविक रूप से तो राज्य की कल्पना के अंतर्गत लौकिक राज्य की ही कल्पना है। हमारे यहां धर्मगुरु को कभी राजा का स्थान नहीं मिला है। राजा स्वयं किसी भी मत का मानने वाला क्यों न हो, सदा सभी मतावलंबियों के प्रति न्याय और समानता का व्यवहार करता था। हां, आज के सेक्यूलरिज्म की कल्पना के अनुसार पक्षपात रहित रहने का अर्थ किसी की मदद न करना नहीं था, अपितु सबकी मदद करना था। अतः राज्य सब मतावलंबियों की

समान रूप से सहायता करता था। इस सहायता के पीछे यह भाव निहित था कि प्रथम तो बिना पारलौकिक उन्नति के लौकिक उन्नति व्यर्थ है तथा दूसरे राजा का कर्त्तव्य है कि प्रजा की सब प्रकार की उन्नति का प्रबंध करे और पारलौकिक क्षेत्र में यह प्रबंध सब मतों को समान सहायता देते हुए उनके आपसी संबंधों को सद्भावनापूर्ण बनाते हुए ही होता था। अतः किसी मत का राज्य न कायम करते हुए भी 'यतो अभ्युदयनिश्रेयसप्राप्ति स धर्मः' की व्याख्या के अनुसार धर्म का विकास करते हुए धर्मराज्य की अवश्य ही स्थापना की जाती थी।

धर्म जीवन है

आज भारतवर्ष के नेतागण यद्यपि पश्चिमी आदर्शों को अपनाकर भावी भारत की रचना करना चाहते हैं और उसके अनुसार पश्चिम के अर्थ में सेक्यूलर स्टेट का अर्थ लौकिक राज्य ही लगाया जा सकता है, किंतु भारतीय जनता धर्मराज्य या रामराज्य की भूखी है और वह केवल लौकिक उन्नति में ही संतोष नहीं कर सकती। भारतीयता की स्थापना भी केवल एकांगी उन्नति से नहीं हो सकती, क्योंकि हमने लौकिक और पारलौकिक उन्नति को एक दूसरे का पूरक ही नहीं तो एक दूसरे से अभिन्न माना है। किंतु पारलौकिक उन्नति के क्षेत्र में राज्य की ओर से किसी एक मत की कल्पना अनुचित होगी। अतः उसे द्वारा ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होगा जिसमें सभी मत बढ़ सकें तथा 'एक' सद्विपाः बहुधा वदन्ति के सिद्धांत का पालन कर सकें।

फलतः हमारे राज्य के लिए 'लौकिक राज्य' सेक्यूलर स्टेट को ठीक पर्याय होने पर भी मौजूद नहीं होगा। धर्म शब्द की उपर्युक्त परिभाषा एवं 'धारणद्धर्ममित्याहुः धर्मोधारयते प्रजा' आदि परिभाषाओं के अनुसार यह शब्द अंग्रेजों के रिलीजन का पर्यायवाची न होकर उससे भिन्न है तथा व्यापक अर्थवाला है। हमारे यहां बिना धर्म के तो किसी के भाव की, उसके अस्तित्व की ही कल्पना कठिन है। फलतः हम समझते हैं कि हमारा राज्य धर्म को तिलांजलि नहीं दे सकता। अतः अधार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, धर्मरहित, धर्महीन, धर्म विरत आदि सभी शब्द न तो हमारे राज्य के आदर्श को ही प्रकट करते हैं और न सेक्यूलर स्टेट ठीक पयार्य हो ही सकते हैं।

मत और धर्म के भेद

अंग्रेज़ों के रिलीजन शब्द का पर्यायवाची शब्द यहां मत है तथा एक मत के मानने वाले को संप्रदाय कहा जाता है, जैसे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, खिस्ती संप्रदाय आदि। निश्चित ही पहले और आज भी राज्य इनमें से किसी एक संप्रदाय का नहीं हो सकता। राज्य की दृष्टि से तो सबके लिए ही समान होनी चाहिए। फलतः हम कह सकते हैं कि राज्य को सांप्रदायिक न होकर असांप्रदायिक होना चाहिए। यही राज्य का सही आदर्श है। ऐसा राज्य किसी सांप्रदाय विशेष के प्रति पक्षपात या किसी के प्रति घृणा का व्यवहार न करते हुए भी जीवन की लौकिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हुए धर्मराज्य हो सकता है।

असांप्रदायिक कहें

'असांप्रदायिक' शब्द से राज्य के ठीक-ठीक आदर्श का ही बात नहीं होता अपितु 'सेक्यूलर' के शाब्दिक नहीं तो पाश्चात्य व्यावहारिक अर्थ के भी यह बहुत निकट है। रूस को छोड़कर किसी राज्य ने कभी रिलीजन (मत) को समाप्त नहीं किया और आज तो रूस में भी पूजा स्वातंत्र्य को मान लिया है यद्यपि राज्य की ओर से किसी को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। शेष सभी राज्यों में सभी संप्रदायों को अपने मत के द्वारा आत्मिक, शारीरिक स्वतंत्रता है तथा इंग्लैंड के राजा को छोड़कर शेष कहीं किसी संप्रदाय विशेष के प्रति पक्षपात नहीं है। अतः उन राज्यों को भी पवित्र रोमन साम्राज्य के विरोध में चाहे लौकिक समझा जाए, किंतु असांप्रदायिक कहना ही अधिक

हमारे यहां बिना धर्म के तो किसी के भाव की, उसके अस्तित्व की ही कल्पना कठिन है। फलतः हम समझते हैं कि हमारा राज्य धर्म को तिलांजलि नहीं दे सकता। अतः अधार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, धर्मरहित, धर्महीन, धर्म विरत आदि सभी शब्द न तो हमारे राज्य के आदर्श को ही प्रकट करते हैं और न सेक्यूलर स्टेट ठीक पयार्य हो ही सकते हैं।

युक्तिसंगत होगा। 'असांप्रदायिक' शब्द के द्वारा हमारे नेताओं का अर्थ भी अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि आज सेक्यूलर शब्द का प्रयोग केवल पाकिस्तान से, जिसने अपने आपको 'इस्लामी राज्य' घोषित किया है भिन्नता दिखाना ही है। भारत 'इस्लामी राज्य' के समान किसी एक संप्रदाय का राज्य नहीं है यही हमारे नेता प्रकट करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सेक्यूलर शब्द को चुना है। आज यद्यपि सांप्रदायिक और राष्ट्रीय शब्दों का ठीक-ठीक ज्ञान न होने के कारण सेक्यूलर शब्द का नाम लेकर रेडियो से गीता और रामायण आदि का पाठ बंद करना आदि अनेक कार्य कर दिए जाते हैं। फिर भी भारतीय राज्य का आदर्श घोषित करते समय हमारे नेताओं के मस्तिष्क में जो प्रधान धारणा रही वह 'असांप्रदायिक' शब्द से ही अधिक व्यक्त होती है।

उपर्युक्त सभी कारणों में से असांप्रदायिक शब्द ही सेक्यूलर का निकटतम भाषांतर है और उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ■

साभारः पांचजन्य (1949)

सुन्दर सिंह भण्डारी: शत शत नमन!

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी का जन्म 12 अप्रैल 1921 को उदयपुर के एक जैन परिवार (राजस्थान) में हुआ। मूलतः उनका परिवार भीलवाड़ा के मण्डलगढ़ से संबंध रखता था, परन्तु उनके दादा वहां से उदयपुर चले गए थे। श्री भण्डारी जी के पिता डा. सुजान सिंह भण्डारी डाक्टरी पेशे से संबंद्ध थे। इस कारण उन्हें सदैव घूमते रहना पड़ता था। श्री भण्डारी की शिक्षा कई स्थानों पर हुई। उन्होंने उदयपुर से सिरोही से इंटरमीडिएट परीक्षा पास की और डीएवी कॉलेज, कानपुर से बीए और एम.ए. किया। उन्होंने अर्थशास्त्र में एम.ए. पास किया और बाद में लॉ का अध्ययन किया।

श्री भण्डारी 'सरल जीवन और उच्च विचारों' के प्रतीक थे। शांत भाव के भण्डारी जीवन भर अविवाहित रहे और राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। 1942 में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मेवाड़ उच्च न्यायालय में लीगल प्रेक्टिस शुरू की। 1937 में उन्होंने एस.डी. कॉलेज, कानपुर में प्रवेश लिया, जहां पं. दीनदयाल उपाध्याय उनके सहपाठी थे। 1937 (दिसम्बर) में इंदौर के बालू महाशब्दे ने उन्हें कानपुर के निकट नवाबगंज की आर.एस.एस शाखा में ले गए थे। तब से वे सदैव अपनी अंतिम सांस तक आरएसएस की विचारधारा के प्रति वचनबद्ध रहे।

श्री सुंदर सिंह भण्डारी ने अनुशासित पार्टी की छवि कायम रखी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जीवन शैली की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। वह एक ऐसे मूर्तिकार और कार्यकुशल क्राफ्टस्मैन थे जिन्होंने मानव, समाज और संगठन की प्रतिमा बनाई। वह कभी भी 'कलश' नहीं बनना चाहते थे। इसी कारण वे अत्यंत स्पष्टवादी थे। अपनी प्रकृति के कारण वे कार्यकर्ताओं में 'हैडमास्टर' के नाम से सुप्रसिद्ध हो गए।

1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, उनका नाम प्रमुख रूप से शामिल किया गया था। 1951 से 1965 तक श्री भण्डारी ने राजस्थान जनसंघ में महामंत्री का दायित्व निभाया। इसके

अलावा वे 1963 में जनसंघ के अखिल भारतीय मंत्री बने थे। पं. दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद 1968 में श्री भण्डारी जी को अखिल भारतीय महामंत्री (संगठन) बनाया गया।

उन्होंने 1977 तक जनसंघ महामंत्री के पद पर कार्य किया। वह 1966-1972 के समय राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए जब वह उस समय 'मीसा' के अन्तर्गत हिरासत में थे। 1998 में उनका राज्य सभा का कार्यकाल समाप्त हुआ, तब उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 1999 में उन्हें गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया। भण्डारी जी ने कार्यकर्ताओं के सामने सरलता, सहनशीलता और मितव्ययता का उदाहरण पेश किया। लोगों ने भी ही उनकी जीवन शैली पर चलना कठिन समझा हो, परन्तु वे प्रकृति से बहुत नरम दिल इंसान थे।

उन्होंने अनुशासित पार्टी की छवि कायम रखी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जीवन शैली की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। वह एक ऐसे मूर्तिकार और कार्यकुशल क्राफ्टस्मैन थे जिन्होंने मानव, समाज और संगठन की प्रतिमा बनाई। वह कभी भी 'कलश' नहीं बनना चाहते थे। इसी कारण वे अत्यंत स्पष्टवादी थे। अपनी प्रकृति के कारण वे कार्यकर्ताओं में 'हैडमास्टर' के नाम से सुप्रसिद्ध हो गए।

22 जून 2005 को उनका स्वर्गवास हो गया। श्री भण्डारी जी ने अपने कालकाजी निवास पर प्रातः पांच बजे अंतिम सांस ली। उन्होंने अपना सारा जीवन मातृभूमि को समर्पित किया तथा जीवन भर के रा.स्व.सं. प्रचारक बने रहे। उनकी मृत्यु से एक प्रखर राष्ट्रवादी समाप्त हो गया। देश ने एक असाधारण राष्ट्रवादी गंवा दिया। भाजपा ने उनकी मृत्यु से एक कुशल संगठक, चिंतक और मार्ग-निर्देशक खो दिया। ■

'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' बनाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं: रामलाल

भाजपा के 37 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कमल संदेश के कार्यकारी संपादक डा. शिव शक्ति बक्सी ने भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल से संगठन से संबंधित विषयों तथा हाल में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी को मिले प्रचंड जनादेश के संदर्भ में आगामी कार्य-योजना पर चर्चा की। प्रस्तुत है मुख्य अंश:

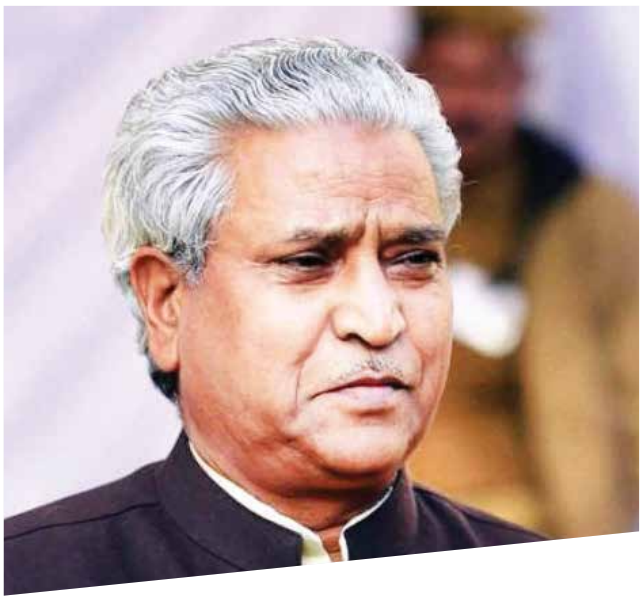

हाल में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को जबर्दस्त जनादेश मिला। इस जनादेश का पार्टी एवं कार्यकर्ताओं के लिये क्या संदेश है?

निश्चित ही पांच राज्यों के चुनावों में बहुत बड़ी सफलता मिली है। 4 राज्यों में हमने सरकार बनाई है। हमारे विधायक और वोट दोनों ही बढ़े हैं। सभी वर्गों का वोट मिला है। विशेष रूप से **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरीब समर्थक नीतियों, योजनाओं से देश के गरीब वर्ग में केन्द्र सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री व अन्य नेतृत्व के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है, वह पार्टी के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।** इससे जाति, वर्ग सम्प्रदाय की राजनीति से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया है, उसे समझने की आवश्यकता है।

अभी तक चुनाव में छोटे-छोटे स्थानीय मुद्दे प्रभावी हो जाते थे। अब देश की जनता सुशासन, विकास व लोक कल्याण की राजनीति की तरफ बढ़ रही है। यह लोकतंत्र की मजबूती हेतु भी शुभ लक्षण है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में तीन-चौथाई से अधिक बहुमत मिलना अपने आप में कीर्तिमान है। 2014 के तुरंत बाद से ही संगठनात्मक तैयारी, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की योजना, परिवर्तन यात्राओं आदि के माध्यम से जहां कार्यकर्ता खड़ा हुआ, वहीं जनता का भी मन बना। **कार्यकर्ता उत्साहित हो, संगठन व्यवस्थित हो, नेतृत्व पर जनता का भरोसा हो तथा चुनाव प्रबंधन चुस्त-दुरुस्त हो तो मन को मत में बदलना तथा उसे पोलिंग बूथ तक पहुंचाना आसान हो जाता है।** यही हुआ भी है। गोवा व मणिपुर में सीटें कम मिलीं, किन्तु सर्वाधिक वोट भाजपा को जनता ने दिया। इसलिए स्थिर सरकार बनाने का प्रयास हमारी राजनैतिक जिम्मेदारी थी, जिसे निभाने में पार्टी नेतृत्व सफल रहा। राजनीति में सोने वालों को सफलता नहीं मिलती, सतत् जागरूक लोग ही सफल होते हैं।

इन राज्यों में सफलता पर कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 12 मार्च को जो कहा वह बहुत महत्वपूर्ण है कि पेड़ में ज्यादा फल लगते हैं तो वह झुका हुआ रहता है। विनम्रता के साथ सफलता। हमें किसी भी तरह की सफलता को अंतिम पड़ाव मानकर संतोष मानने की आवश्यकता नहीं। प्रेरणा लेकर नए उत्साह के साथ और आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करना यही भाजपा के कार्यकर्ताओं का मूल पिंड है। 2014 की सफलता के पश्चात् हमने प्रारम्भ से ही आगे की तैयारी प्रारम्भ की है। जिन राज्यों में हमारा ढांचा कमजोर रहा है, वहां मजबूती के विशेष प्रयास हुए हैं। परिणामस्वरूप असम में आज भाजपा के नेतृत्व की सरकार है तथा उड़ीसा में भी पंचायत चुनावों में अच्छी सफलता मिली है। जो वातावरण बना है उसका लाभ निश्चित रूप से संगठन विस्तार, सुदृढ़ता तथा चुनावी राजनीति में भी प्रभाव बढ़ाने में मिलेगा।

अब भाजपा 'पार्टी ऑफ गवर्नेंस' बन गई है, जिससे कार्यकर्ताओं

का दायित्व भी कई गुणा बढ़ गया है। बदले हुए परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ता अपने दायित्व का पालन कैसे करें?

आपने कहा भाजपा 'पार्टी ऑफ गवर्नेंस' बन गई है। यह एकदम ठीक बात है। हर पार्टी की अपनी पहचान बनती है। डा. मुखर्जी का बलिदान राष्ट्र की एकता-अखंडता की रक्षा के लिये हुआ, आपातकाल के समय लोकतंत्र की रक्षा के लिये हजारों कार्यकर्ता जेल गये तथा कई बलिदान हुए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिये संघर्ष (लालकृष्ण आडवाणी जी द्वारा यात्रा), राष्ट्रीय गौरव की रक्षा हेतु डा. मुरली मनोहर जोशी द्वारा तिरंगा यात्रा तथा एनडीए-1 में अटलबिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण विस्फोट आदि।

एनडीए-1 से विकास की जो यात्रा प्रारम्भ हुई उसे भाजपा शासित प्रांतों ने बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। विशेष रूप से गुजरात प्रदेश नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन व विकास का प्रतीक बन गया। आज भी प्रदेश सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अधिकांश विषयों में प्रथम पांच में भाजपा शासित राज्य ही रहेंगे।

आज भाजपा के सबसे अधिक सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री हैं। 16 राज्यों में भाजपा सरकार में है। एनडीए से 17 राज्य जुड़े हैं। भारत का लगभग 60 प्रतिशत भू-भाग भाजपा शासन से जुड़ा है। यह यात्रा कठिन थी, संघर्षपूर्ण थी, किन्तु सभी ने चुनौती को अवसर मान कर कार्य किया, परिणामस्वरूप इतना बड़ा रूप सामने है। हमारा प्रयास है इसी मानसिकता से तथा जीत से उत्साह लेकर हम और आगे बढ़ेंगे।

2014 में केन्द्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने के पश्चात् तो **नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सुशासन व विकास के तथा गरीब कल्याण के नाते पहचान बनाने तथा लोगों का विश्वास जीतने में सफल हुई है।** यह सरकार कड़े फैसले, राष्ट्र हित में फैसले, निर्णायक सरकार के रूप में जानी जाती है। देश के बहादुर सैनिकों द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, नीम कोटेड यूरिया, फसल बीमा योजना, मुद्रा योजना के अंतर्गत 6.6 करोड़ लोगों को ऋण, उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक 2 करोड़ गैस कनेक्शन, 27.97 करोड़ जन धन खाते, बाबा साहब के सम्मान में भीम एप का शुभारम्भ, अभी तक 2 करोड़ भीम एप डाउनलोड, आसान कर-प्रणाली 'जीएसटी' का पारित होना, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा, स्किल इंडिया, सस्ती जेनेरिक दवाओं की दुकानें, उजाला योजना के तहत 21.8 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण, 12586 गांवों को पहली बार बिजली से जोड़ा जाना और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।

पार्टी का पूरे देश में विस्तार की योजनाएं बनीं जिसका परिणाम भी सामने आने लगा है। आगामी वर्षों में किस प्रकार की संगठनात्मक योजना है?

हमने पार्टी के विस्तार की दृष्टि से सदस्यता अभियान चलाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन तथा सभी कार्यकर्ताओं की एकजुट मेहनत का परिणाम है कि भाजपा देश ही नहीं दुनिया की सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी बन गई।

हमने कमजोर राज्य, जिले व मंडल चिह्नित करके उनके लिये विशेष कार्य-योजना बनाई, मंडल तक प्रशिक्षण अभियान चल रहा है। आगे भी यह गति निरंतर बढ़ती रहे यही प्रयास होगा। विभिन्न प्रदेश इकईयां बूथ तक संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने व मजबूत करने में लगी है। बूथ पर छह कार्यक्रमों की रचना भी बनी है, जिससे बूथ इकाई की सक्रियता व उससे संवाद बना रहे।

अन्य पार्टियों से यदि तुलना करें तो भाजपा का निरंतर विस्तार हुआ है। संसद में 2 से 282 सीटों तक की यात्रा को आप कैसे देखते हैं?

आपने पूछा है 2 से 282 सांसद होने की यात्रा के बारे में। 1984 में केवल दो सांसद जीतना एक कठिन समय था। ऐसे समय निराशा में डूबकर बैठा जा सकता था या **हिम्मत के साथ चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने को सोचा** जा सकता था। नेतृत्व ने आगे बढ़ने का रास्ता चुना। नेताओं के प्रवास, संगठनात्मक कार्यक्रम, विभिन्न आंदोलन, जनता से संवाद के द्वारा कार्य प्रारम्भ हुआ तो 1989 में ही उसका परिणाम आ गया। 2004 व 2009 को छोड़ दें तो हम निरंतर बढ़ते रहे। आज भाजपा के सबसे अधिक सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री हैं। 16 राज्यों में भाजपा सरकार में है। एनडीए से 17 राज्य जुड़े हैं। **भारत का लगभग 60 प्रतिशत भू-भाग भाजपा शासन से जुड़ा है।** यह यात्रा कठिन थी, संघर्षपूर्ण थी, किन्तु सभी ने चुनौती को अवसर मान कर कार्य किया, परिणामस्वरूप इतना बड़ा रूप सामने है। हमारा प्रयास है इसी मानसिकता से तथा जीत से उत्साह लेकर हम और आगे बढ़ेंगे।

हाल ही में पार्टी में 19 विभागों एवं कई प्रकल्पों का गठन हुआ है। इससे पार्टी कार्य को किस प्रकार की दिशा एवं गति मिली है?

पार्टी का कार्य समाज के सभी घटकों तक पहुंचे तथा कुछ निश्चित विषयों पर विशेष ध्यान रहे इस दृष्टि से प्रकोष्ठ, विभाग व प्रकल्पों की रचना की गई है। इससे focused area व विषय विशेष की ओर ठीक प्रकार से कार्य होता है। कार्यालय निर्माण, कार्यालय आधुनिकीकरण, पुस्तकालय आदि विषयों में ठीक दिशा में कार्य प्रारम्भ

हुआ है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, नमामि गंगे विषय भी आगे बढ़े हैं। इससे अनेक नये लोग जुड़ रहे हैं तथा नये क्षेत्रों में भी प्रवेश हो रहा है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष पार्टी किस प्रकार से मना रही है?

पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष हेतु जिलों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संचालन समितियां बनी हैं। सरकारें अपने-अपने ढंग से कार्यक्रम कर रही हैं। संगठन के स्तर पर भी कार्य की दिशा स्पष्ट है- दीनदयाल जी के व्यक्तित्व, विचार, व्यवहार की चर्चा, समाज कल्याण विशेष रूप से अंत्योदय (गरीब कल्याण) हेतु सभी कार्यकर्ताओं द्वारा निजी रूप से एक शुभ संकल्प लेना, संगठन के विस्तार व कार्यकर्ताओं के विकास की योजना। एक विशेष योजना बनी है- **पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कार्य विस्तार योजना।** इसके अंतर्गत 6 माह से 1 वर्ष तक के लिये शताब्दी विस्तारक निकलेंगे। साथ ही बड़ी संख्या में (1 लाख तक) 15 दिन के लिये शताब्दी अल्पकालीन विस्तारक निकलेंगे। हर प्रांत 6 अप्रैल से 6 जुलाई के मध्य 15 दिन का समय निश्चित करके महा-सम्पर्क की योजना करने वाला है। **हर घर तक दीनदयाल जी का चित्र, स्टिकर व एक फोल्डर (विचार और व्यक्तित्व को लेकर) पहुंचे तथा केन्द्र व प्रदेश सरकारों की उपलब्धियां व पार्टी के विचार को भी घर-घर तक पहुंचाने की योजना बनी है।** अन्य विभिन्न कार्यक्रम प्रांतों की योजनानुसार होंगे।

भाजपा स्थापना दिवस 6 अप्रैल 2017 के अवसर पर आपका पार्टी कार्यकर्ताओं के लिये क्या संदेश है?

6 अप्रैल पार्टी का स्थापना दिवस है। 37 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन वर्षों में कई तरह के उतार-चढ़ाव पार्टी ने देखे हैं, फिर भी आगे बढ़ने का संकल्प निरंतर बना रहा। जनसंघ से लेकर आज तक नेतृत्व से लेकर साधारण कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या, बलिदान से यह पार्टी खड़ी हुई है। अकेले केरल के 1 जिला (कन्नूर) में ही अब तक अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। आज हम संकल्प लें कि राष्ट्र व समाज के लिये समर्पण भाव से कार्य करेंगे। हमारे लिये राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय तथा स्वयं आखिर में रहेगा। **हमारी प्रेरणा एकात्म मानव दर्शन तथा अंत्योदय होगी। हमारी सोच में सबका साथ-सबका विकास रहेगा। एक भारत- श्रेष्ठ भारत हमारी दिशा रहेगी। हमारे हाथ से वही कार्य होगा जिस कार्य से भारत की मान प्रतिष्ठा बढ़े और हो 'भारत माता की जय'।** ■

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को मंजूरी

ओबीसी सांसद प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्रीजी से मिलकर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 मार्च को बड़ा फैसला करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को मंजूरी दे दी। इसकी जगह नया आयोग बनाया जाएगा। वह नया आयोग ओबीसी में नई जातियों को जोड़ने के लिए बनायी जाएगी।

वरिष्ठ भाजपा नेता श्री हुकुमदेव नारायण, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री भूपेन्द्र यादव, श्री संजय जायसवाल, श्री रमेश वैश्य, श्री गणेश सिंह के नेतृत्व में ओबीसी सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्रीजी से मिलकर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। समाज में गरीबों एवं पिछड़े वर्गों के समतामूलक व्यवस्था देने में यह एक अभूतपूर्व कदम है जो न्यायपूर्ण भारत का निर्माण करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश के सामाजिक और शैक्षिक रूप

से पिछड़े वर्ग के लिए यह एक ऐतिहासिक, न्यायपूर्ण एवं सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ■

भाजपा राष्ट्रीय मीडिया विभाग प्रमुख एवं सह–प्रमुख नियुक्त

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 31 मार्च को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अनिल बलूनी को मीडिया विभाग का राष्ट्रीय प्रमुख एवं बिहार विधान परिषद् के सदस्य श्री संजय मयूख को राष्ट्रीय सह–प्रमुख नियुक्त किया। ■

पूरे देश में एक जैसी टैक्स प्रणाली होगीः अरुण जेटली

केंद्रीय वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली ने लोक सभा में 29 मार्च को जीएसटी से संबंधित चार विधेयक प्रस्तुत किए। दिन भर सारगर्भित चर्चा के दौरान सांसदों ने जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। विधेयक प्रस्तुत करते समय और चर्चा के बाद श्री जेटली ने जीएसटी की कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला। यहां प्रस्तुत है उनके द्वारा कही गई बातों का सारांश—

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली ने विधेयकों पर विचार किए जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए लोक सभा में 29 मार्च को कहा कि केन्द्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017, एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक, 2017, माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017 महत्वपूर्ण चार विधेयक हैं जिनको संयुक्त रूप से इसलिए लिया जा रहा है कि इनका सब्जैक्ट मैटर और संदर्भ एक जैसे हैं। संविधान के 101 वें संशोधन से पूर्व इस देश में जो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली थी, वह प्रणाली आज भी चली आ रही है और इस वर्ष 15 सितम्बर तक चलेगी, उसके तहत कुछ टैक्सेज केन्द्र को लगाने का अधिकार था, कुछ टैक्सेज राज्यों को लगाने का अधिकार था। परन्तु इन विधेयकों का उद्देश्य है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं, पूरे देश के अंदर उनका आवागमन हो पाएगा। पूरे देश में एक जैसी टैक्स प्रणाली होगी तथा एक असैसी का इंटरफेस केवल एक असैसिंग अथारिटी के साथ होगा और उसमें से जो टैक्स निकलेगा, वह केन्द्र और राज्य आपस में बांट लेंगे। यह व्यवस्था पहले की व्यवस्था से थोड़ा भिन्न है। यह भिन्न इसलिए है कि हम विधि द्वारा केन्द्र और राज्य दोनों के लिए एक साथ एक क्षेत्राधिकार सृजित कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में हम अप्रत्यक्ष कर प्रशासन की जिम्मेदारी एक ऐसी प्रथम संघीय संस्था को सौंप रहे हैं जिसकी स्थापना भारत द्वारा की गई है और जिसमें केन्द्र और राज्य दोनों प्रतिभागी होंगे। इस संबंध में माल और सेवा कर परिषद ने सर्वसम्मति से पांच कानूनों के संबंध में अपनी सिफारिश भेजी है, जिसमें चार संसद के सामने आएंगे और एक हर राज्य की विधान सभा और दो यूनियन टेरिटरिज, जिनमें विधान सभाएं हैं, उनके सामने आएगा। पहला कानून है, सेंट्रेल जीएसटी लॉ जिसके अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे इंटीग्रेट करना, कर की ऊपरी सीमा तय करना, टैक्स को इकट्ठा करना आदि सम्मिलित है।

दूसरा कानून एसजीएसटी लॉ है, जो केन्द्र के सामने नहीं आएगा बल्कि 31 विधान सभाओं के सामने जाएगा, जो सेंट्रल लॉ का एक प्रकार से मिरर इमेज होगा कि हर राज्य में जीएसटी किस प्रकार

से लगेगा। तीसरा कानून इंटीग्रेटिड जीएसटी है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक यूनियम टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, तो उस संबंध में जो इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर टैक्स लगता है, वह उसका संचालन करेगा। चौथा कानून यूनियन टेरिटरी जीएसटी लॉ है जो एक प्रकार से सीजीएसटी लॉ है, क्योंकि यह उसके प्रावधानों को इनकारपोरेट कर लेता है और उन्हें यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लागू करता है। पांचवां और अंतिम कानून उस व्यवस्था से संबंधित है जिसके अंतर्गत उस राज्य को मुआवजा प्रदान करने का उपबंध किया गया है, जिसे इसमें घाटा होता है। ऐसे राज्यों को मुआवजा प्रदान करने के लिए मुआवजा उपकर का प्रावधान किया गया है जिसमें लग्जरी आइटम्स पर 28 प्रतिशत से अधिक की कराधान राशि सम्मिलित होगी। इसके अतिरिक्त माल और सेवा कर परिषद भारत की ऐसी प्रथम संघीय संस्था है जिसमें अप्रत्यक्ष करों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र और राज्यों की संप्रभुता एक साथ संग्रहीत की गई है। अतः भारत की पहली संघीय संस्था स्थापित करने के लिए हम सभी के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि यह संघीय संस्था कार्य करे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम उस संबंध में नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं इस विधि को सदन के विचारार्थ संस्तुति करता हूं।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण

जेटली) ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि एक बार यह विधेयक अधिनियम बन जाये और लागू हो जाये तो भारत की कर प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हमारी वर्तमान प्रणाली में अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं तथा अनेक कर निर्धारण अधिकारी हैं। आज आर्थिक गतिविधियां बदल रही हैं, क्योंकि प्रकृति से ऐसे अनेक कर मिल रहे हैं। यद्यपि, 1947 में हम एक राष्ट्र बन गए, भारत में अनेक आर्थिक क्षेत्र रहे हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी कर और कर दरें रही हैं जिसके कारण बहुत से आर्थिक स्रोत गुम हो गए हैं। देश में वस्तु और सेवाओं का निर्बाध प्रवाह नहीं है। जीएसटी का उद्देश्य एक कर लगाना है जिसके द्वारा एक करदाता को एक अधिकारी के साथ केवल एक इंटरफेस हो। इसको अधिक सक्षम कर बनाना चाहिए, जिसका उल्लंघन करना आसान न हो ताकि इसका अनुपालन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। भारत के संविधान द्वारा केन्द्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची के माध्यम से केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यदि केन्द्र इसका उपयोग करता है तो उसी शक्ति काम करती है। शक्तियों के बंटवारे में कोई ग्रे क्षेत्र नहीं था।

वास्तव में, जीएसटी का विचार ग्रे क्षेत्र दिया। ग्रे क्षेत्र यह है कि आपके पास एक कर है जिसे केन्द्र और राज्यों के द्वारा सम्मिलित रूप से लगाया जाएगा। यह एक कर होगा। केन्द्र और राज्य अपने सभी करों को उस एक कर में मिला देंगे। एक कर में केन्द्र और राज्यों की शक्ति बनी रहेगी। केन्द्र और राज्यों के बीच में संप्रभुता साझा की जाती है। हमने भारत का पहला संघीय निर्णय लेने वाला प्राधिकरण बनाया है। पूलकृत संप्रभुता के द्वारा केन्द्र और राज्य मिलकर निर्णय करेंगे कि कर दर क्या हों, कानून कैसा हो और इनको लागू कैसे किया जाए। आज, हमारे यहां करों के ऊपर कर हैं, जिससे वस्तुएं महंगी हो गयी हैं। यदि एक बार इनको हटा दिया जाए तो वस्तुएं सस्ती हो जायेंगी। कानून बनाने और दरें लागू करने की सिफारिश परिषद् करेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत जीएसटी परिषद् कर की दरों के निर्धारण की सिफारिश करेगी। जीएसटी परिषद् को आदर्श विधि की बाबत सिफारिश करने की शक्ति अनुच्छेद 279(क) से प्राप्त हुई है। इस बारे में संसदीय नियंत्रण होगा। वार्षिक वित्तीय विवरणों और वित्त विधेयक में शामिल हुए कर की दरों पर राज्य विधायिका का नियंत्रण होगा। सामान्यतः इन सिफारिशों को माना जाना चाहिए और यदि ये नहीं मानी जाती हैं, तो इन्हें पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जायेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 246(क) और अनुच्छेद 279(क) को उनकी सामंजस्यता के साथ पढ़ा जाये। अतः अनुच्छेद 265 जिस विधि के प्राधिकार की बात करता है, वह प्राधिकार अनुच्छेद 246(क) के तहत बने कानून को प्राप्त है, जिसे संसद और राज्य विधायिकायें जीएसटी परिषद् की सिफारिशों पर अनुमोदित करेंगी। इस तरह अनुच्छेद 265 के अनुरूप इसे विधि का प्राधिकार है। सरकार ने राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिये कराधान फार्मूला के स्थान पर उपकर का फार्मूला अपनाया है। यदि सरकार ने कराधान का फार्मूला अपनाया होता, तो करों के जरिये क्षतिपूर्ति के वित्तपोषण के लिये कुल कर प्रभाव अस्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होता। केन्द्र सरकार को क्षतिपूर्ति के वित्त पोषण को 50,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिये 1.72 लाख करोड़ रुपये का कर लगाना पड़ता। इस फार्मूला में उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त कर बोझ नहीं पड़ेगा। यह अस्थायी रूप से 5 वर्षों के लिये है, ताकि संबंधित क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिये इसका प्रयोग किया जाएगा। कुछेक माननीयों ने यह प्रश्न उठाया है कि यह धन विधेयक क्यों है। यह विधेयक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि, सेवा कर विधि, मूल्यवर्धित कर विधि तथा अनेक अन्य कराधन विधियों के स्थान पर लाया गया है।

यह इन सबों की एक समेकित विधि है। संविधान की धारा 110 के अंतर्गत अगर किसी विधेयक द्वारा कराधान का आरोपन होता है

एक कर में केन्द्र और राज्यों की शक्ति बनी रहेगी। केन्द्र और राज्यों के बीच में संप्रभुता साझा की जाती है। हमने भारत का पहला संघीय निर्णय लेने वाला प्राधिकरण बनाया है।

तो वह धन विधेयक है। कुछ सदस्यों को मुनाफा अर्जन रोधी खंड के विचार पर कुछ आपत्ति थी। मुनाफा अर्जन रोधी खंड वही है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कराधान के कारण अनुचित रूप से समृद्ध नहीं हो सकता। अतः यदि किसी व्यक्ति को कर में छूट मिलती है उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इस विधेयक में यही मुनाफा अर्जन रोधी खंड है। मोइली साहब ने जो तर्क दिया, वह बिल्कुल सही तर्क था कि रियल स्टेट में भी कर चोरी होती है। अतः रियल स्टेट को भी जीएसटी में लाने का प्रयास करना चाहिए। जैसाकि मैंने कहा कि यह फेडरल बॉडी है और इसमें राज्यों को साथ लेकर चलना है तो राज्यों को इस बात की आशंका थी कि अगर इसमें रियल स्टेट आ गया तो राज्यों को स्टाम्प डयूटी कलेक्शन वगैरह पर इसका असर पड़ेगा। तत्पश्चात्, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने एक पत्र तैयार किया जिसमें यह लिखा गया राज्य स्टाम्प डयूटी और अन्य राजस्व जिसे वे इस माध्यम से प्राप्त करते हैं, अपने पास रख सकते हैं। दिल्ली के वित्त मंत्री ने परिषद के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति पेश की जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि रियल स्टेट को भी शामिल किया जाए। उनकी बात एवं उनके अभ्यावेदन सुनने के पश्चात् परिषद ने निर्णय किया। 'जीएसटी को लागू होने दीजिए। पहले ही वर्ष हम इस बात पर विचार करेंगे कि रीयल स्टेट को इसके अंदर लायें अथवा नहीं।' यही स्थिति पेट्रोलियम उत्पादों एवं सेवन/खपत किये जाने वाले अल्कोहल की है।

राज्यों का कहना था हमारा इसमें बड़ा रिवेन्यू है और हम पेट्रोलियम उत्पाद तथा अल्कोहल पर सहमत नहीं हो सकते। चर्चा के बाद हमने राज्यों को राजी किया कि चलिए, हम अल्कोहल को नहीं छूते हैं, लेकिन पेट्रोलियम को जीएसटी के संविधान संशोधन विधेयक में लाने दीजिए। आज पेट्रोलियम संवैधानिक रूप से जीएसटी के अंतर्गत है, परंतु इसकी जीएसटी शून्य दर वाली है।

एक बार जीएसटी का प्रयोग आगे बढ़ जाये, तो परिषद को संविधान में संशोधन के बिना यह अवसर मिलेगा कि पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में क्या निर्णय लिया जाये। कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर काउंसिल व राज्यों में शंकाएं थीं। अभी तक जिस तरह से काउंसिल चली है, उसको देखकर मैंने भी यह उपयुक्त समझा है कि जिन-जिन निर्णयों पर आम राय बन जाय, उसी पर हम निर्णय लेते हैं। राजस्व सेवा की समीक्षा थी कि जहां तक आईजीएसटी का प्रश्न है, यह पूर्णतः केंद्र द्वारा शासित है। उन्होंने संविधान को उद्धृत करते हुए बताया तथा यह तथ्य भी है कि यदि दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो दोनों में से कोई राज्य अधिनिर्णायक नहीं होगा। इस पर विस्तृत चर्चा हुई और आम राय पर हम एक नतीजे पर पहुंचे। यदि आप संविधान के अनुच्छेद 258 को देखें, यदि केन्द्र को कराधान संबंधी कोई कार्य करना है, जो कि आईजीएसटी के अधीन है हम संविधान के अंतर्गत निर्वाह कर सकते हैं। केन्द्र इस शक्ति को किसी एक राज्य को प्रत्यायोजित करने के लिये अधिकृत है। अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिसमें पश्चिमी बंगाल सरकार भी शामिल है, इस शक्ति को राज्यों के साथ ही बांटने हेतु बहुत सजग है और चाहती है कि यह शक्ति केवल केन्द्र के हाथों में न हो। काउंसिल ने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाया। मैंने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साथ एक बैठक की और उनको संप्रेषित किया कि आपके अधिकार और शक्तियां गैर चुनौतीपूर्ण और अपरिवर्तनीय रहेंगे, परंतु आपकी शक्ति के स्रोत संविधान और अधिनियम में निहित होंगे। यह क्षेत्राधिकार बना रहेगा। अगर आपने कांट्रेक्ट लेबर हायर किया है, लेकिन इसका अर्थ यही नहीं है कि जिसको आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मानते हैं जिनका अभी आप जिक्र कर रहे हैं उन पर टैक्स लगेगा। वे प्रोडक्ट्स अभी भी जीरो रेटेड रह सकते हैं और आप भी इसको इसी दृष्टि से देखिये। मुझे लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये प्रोड्क्टस जीरो रेटेड में रहने वाले हैं। बहु पंजीकरण से छूट के संबंध में खंड 148 के अंतर्गत एक ओवरराईडिंग शक्ति विद्यमान रखी गई है। केन्द्र सरकार इसके मूल्य निर्धारण नहीं करती, केवल इन दरों को अधिसूचित करती है। महोदया, यह काउंसिल एक स्थायी निकाय होगा और इस स्थाई निकाय में सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे। ■

'आय से अधिक संपत्ति मामले में वीरभद्र सिंह इस्तीफा दें'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेन्द्र यादव ने 2 अप्रैल को कहा कि कांग्रेस में नैतिकता का अभाव और भ्रष्टाचार का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि न्यायालय द्वारा श्री वीरभद्र सिंह के निर्णय के बाद भी कांग्रेस क्यों मौन है उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में जरा सी भी नैतिकता है तो उन्हें श्री वीरभद्र सिंह का तुरंत पद से इस्तीफा लेना चहिए। उन्होंने कहा कि श्री वीरभद्र सिंह जो वर्तमान में हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार व आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप उस समय से हैं जब से वो केन्द्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी प्रारंभिक जांच में यह पाया कि श्री वीरभद्र सिंह ने अपने खातों (income tax return) में यह दिखाया है कि वर्ष 2008-09 और वर्ष 2010-11 के दौरान उनके सेब के बागों का मुनाफा 6 करोड़ से ज्यादा था, जबकि उससे पहले के और उसके बाद के सालों में उनका मुनाफ़ा शून्य था। यह तथ्य स्वतः ही यह बताने में काफी है कि श्री वीरभद्र सिंह ने अपनी 'काली कमाई' को छुपाने के लिए अपने खातों में अपने 'सेब के बागों' की कमाई को अवैध रूप से दिखाया।

श्री वीरभद्र सिंह ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर भ्रष्टाचार के केस के विरुद्ध एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में डाली थी जिसका निर्णय दिनांक 31-03-2017 को आया है और अपने निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने श्री वीरभद्र सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है तथा उनके विरुद्ध दायर की गई एफ.आई.आर. को सही माना है।

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपनी अन्वेषण की कार्यवाही के दौरान श्री वीरभद्र सिंह के निवास स्थान पर मारे गए छापों को भी उचित माना है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने यह भी माना है कि श्री वीरभद्र सिंह जी के ऊपर एफ. आई. आर रजिस्ट्रेशन के पीछे किसी प्रकार का दुश्विचार तथा राजनैतिक उद्देश्य नहीं था।

श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि इस मामले में स्टांप पेपर के रजिस्टर पर साधारण ध्यान देने से ज्ञात होता है कि अपने अवैध अनुबंध को उचित ठहराने के लिए, इसमें अवैध रूप से जाली एंट्री की गई हैं। स्टांप पेपर रजिस्टर पर की गई कटिंग यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि इसमें कुछ प्रविष्टियां बाद की तारीखों पर की गई हैं। जिस तरीके से आनंद चौहान (एजेंट-वीरभद्र सिंह) ने इस रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए उसमें और रजिस्टर में पूर्व में की गई प्रविष्टियों के हस्ताक्षरों में विरोधाभास प्रकट होता है। उससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रविष्टियां बाद की तारीखों पर उस स्थिति में की गईं जब इनकम टैक्स विभाग द्वारा उन पर कार्यवाही की गई।

इन उपरोक्त तथ्यों से श्री वीरभद्र सिंह का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना न केवल नैतिक, अपितु सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं के भी विरुद्ध है। वे भ्रष्टाचार से कांग्रेस के समझौते के प्रतीक बन गये हैं। भाजपा मांग करती है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से त्याग-पत्र देना चाहिए। ■

प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में चेनानी-नाशरी सुरंग राष्ट्र को समर्पित की

एशिया में द्वि-दिशात्मक राजमार्ग की सबसे लंबी सुरंग

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में भारत की सबसे लंबी चेनानी-नाशरी राजमार्ग सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में, उन्होंने कहा कि इस सुरंग से न सिर्फ जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि घाटी में पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य में विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सड़क परिवहन, राजमार्ग और नौवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी और उनकी टीम को इस सुरंग के निर्माण के लिए धन्यवाद दिया और राज्य के विकास के लिए अपने श्रम का योगदान करने के लिए युवाओं की सराहना की।

श्री मोदी ने कहा कि ये सुरंग हजारों करोड़ रुपयों की लागत से बनी है। लेकिन मैं आज गर्व से कहता हूं, भले इस सुरंग के निर्माण में भारत सरकार के पैसे लगे होंगे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस सुरंग के निर्माण में भारत सरकार के पैसों के साथ जम्मू-कश्मीर के नौजवानों का पसीने की उसमें महक आ रही है। ढाई हजार से ज्यादा युवकों ने, जम्मू-कश्मीर के 90 प्रतिशत जवान जम्मू-कश्मीर के हैं; जिन्होंने काम करके ये सुरंग का निर्माण किया है। रोजगार की कितनी संभावनाएं उपस्थित हुई, ये हम अंदाज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के जिन नौजवानों ने इन पत्थरों को काट-काट करके सुरंग का निर्माण किया, एक हजार दिन से ज्यादा दिन-रात मेहनत करके वो पत्थरों को काटते रहे और सुरंग का निर्माण करते रहे। मैं कश्मीर घाटी के नौजवानों को कहना चाहता हूं, पत्थर की ताकत क्या होती है; एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं घाटी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने दो रास्ते हैं जो आपके भाग्य को किस दिशा में ले जाएंगे? एक तरफ है पर्यटन, दूसरी तरफ है आतंकवाद। 40 साल हो गए अनेक निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, किसी का फायदा नहीं हुआ; अगर लहुलुहान हुई तो मेरी अपनी प्यारी कश्मीर घाटी हुई है। अगर कोई लाल खोया है तो मेरी कश्मीर की मां का लाल हमने खोया है, कोई हमने हिन्दुस्तान का लाल खोया है। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व के अंतर्गत यह एक नये भारत का शुभारंभ है। जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी राज्य के लिए सहायता बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया।

भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया'और 'कौशल इंडिया' पहल के एक आदर्श उदाहरण के रूप में जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर और रामबन के बीच वाहनों की आवाजाही के लिए सभी मौसम के अनुकूल नौ किलोमीटर लंबी यह सुरंग न सिर्फ भारत की सबसे लंबी सुरंग है, बल्कि एशिया में द्वि-दिशात्मक राजमार्ग की सबसे लंबी सुरंग भी है। दुर्गम हिमालय के सबसे कठिन मार्गों में से एक के तौर पर इसे 1200 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह सुरंग 41 किलोमीटर की सड़क दूरी को कम करते हुए जम्मू से श्रीनगर के बीच यात्रा के समय में दो घंटे की कमी लाएगी। भारी ट्रैफिक जाम, भूस्खलन, बर्फबारी, तीव्र मोड़ और वाहनों एवं दुर्घटनाओं के कारण होने वाली बाधाओं को देखते हुए इस सुरंग से जाने वाले यात्री सभी मौसमों में आसानी से अपनी यात्रा कर सकेंगे। यह सुरंग जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के 246 किलोमीटर लंबे चार लेन मार्ग का एक हिस्सा है। इस सुरंग के साथ-साथ एक समकक्ष मार्ग भी तैयार किया गया है, जो आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रियों को निकालने का काम करेगा। पूरी सुरंग के साथ-साथ 29 रास्ते इन आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार किए गए हैं। सुरंग के दोनों सिरों पर टोल प्लाजा के साथ चार लेन की सड़क और इसके दक्षिण और उत्तरी सिरे पर दो छोटे सेतु भी हैं। सुरंग में अधिकतम पांच मीटर तक की ऊंचाई के वाहन जा सकते हैं। इनकी जांच के लिए सुरंग के दोनों सिरों पर ऊंचाई के लिए विशेष सेंसर लगाए गए हैं।

सुरंग में एक कुशल वायु निकास की प्रणाली भी लगाई गई है। हर आठ किलोमीटर की दूरी पर ताजा वायु अंदर आने और हर सौ मीटर की दूरी पर प्रदूषण बाहर निकालने की व्यवस्था भी की गई है। सुरंग में वेंटीलेशन, संचार, बिजली आपूर्ति, दुर्घटना की जानकारी, एसओएस कॉल बॉक्स और अग्निशमन के लिए एक पूर्ण स्वचालित प्रणाली स्थापित की गई है। यह सुरंग पूरी तरह से स्वचालित स्मार्ट नियंत्रण पर आधारित है और इसके संचालन के लिए किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। सुरंग में किसी भी सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्कैनर भी लगाए गए हैं। दुनिया की बहुत कम सुरंगों में इस प्रकार की पूर्ण एकीकृत सुरंग नियंत्रण प्रणाली स्थापित है।

यह परियोजना पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल भी है। इससे जम्मू-श्रीनगर मार्ग पर समय बचत के साथ-साथ प्रतिदिन करीब 27 लाख रुपये के तेल की भी बचत होगी। ■

कृषि और अम्बेडकर के सपनों का भारत

| वीरेंद्र सिंह मस्त |

कृषि भारत की जीवनधारा है। देश के दो तिहाई से अधिक लोगों कि यह आजीविका है, भले ही देश की जीडीपी में इसका योगदान मात्र 14 प्रतिशत है। मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता किसान हैं। जब किसान खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल बनेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान मैंने किसान संकल्प पत्र प्रदेश की जनता के सामने रखा था और जबकि हमारी सरकार ने वहां काम करना शुरू कर दिया है, पहली ही कैबिनेट बैठक में लघु एवं सीमान्त किसानों के ऋण माफ कर दिए गए हैं। इसी से हमारी प्राथमिकतायें पता चलती है। इस वर्ष गेहूं कि अच्छी पैदावार हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों से 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा आलू के किसानों के लिए एक समिति बनाई गई है जो उनके समस्याओं पर गौर करेगी। जब कभी भी आलू की अधिक पैदावार होती है किसानों को उसकी लागत तक नहीं निकलती। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है कि स्कूल के मध्यान्ह भोजन योजना में आलू को शामिल किया जाए। आलू अपने आप में एक सम्पूर्ण आहार है और इसके जरिये इसकी खपत भी बढ़ जाएगी।

किसानों के ऋण माफी की जो योजना उत्तर प्रदेश की सरकार लायी है, वह दूसरे प्रदेशों के लिए भी रास्ता दिखला सकती है। सरकार ने ऋण माफी की यह रकम बांड के जरिये जुटाने का फैसला किया है। पूर्व की सपा और बसपा कि सरकारों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह ऋण माफी का बोझ उठा सके। सरकार ने लम्बी अवधि के बांड जारी कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया है जिससे कि इन बांडों के पुनर्भुगतान के समय

किसानों के ऋण माफी की जो योजना उत्तर प्रदेश की सरकार लायी है, वह दूसरे प्रदेशों के लिए भी रास्ता दिखला सकती है। सरकार ने ऋण माफी की यह रकम बांड के जरिये जुटाने का फैसला किया है।

अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। योगी सरकार का यह कदम उन गैर भाजपा राज्यों के लिए भी एक सबक है जो हर बात में केंद्र का रोना रोते हैं। इस नीति के तहत ही राज्यों को अपनी योजनायें बनानी होंगी जिससे किसानों को ऋण के संकट से निकाला जा सके।

वर्षों पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किसानों को ऋण के संकट से उबारने के लिए ऐसी ही दृष्टि पेश किया था। इस देश में अमीर और गरीब कि खाई को कैसे कम किया जाए इसी पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। मोदी जी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उससे ज्यादा गरीबों का दर्द भला कौन समझ सकता है। बाबा साहेब के विचारों को कांग्रेस की सरकारों ने लगातार उपेक्षा की। आज हमें उनके विचारों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है जिससे हमारी आर्थिक नीतियां भारत के आर्थिक विकास को संभव बना सके। हम बाबा साहेब के सपनो के आधार पर नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इसी को आधार बनाकर हम 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक देश के सभी पंचायतों तक बाबा साहेब के विचारों को ले जा रहे हैं।

बाबा साहेब कुछ गिने-चुने भारतीयों में से हैं जिन्होंने इतिहास की धारा बदलने के लिए लम्बी लड़ाई लड़ी। अलग-अलग मौके पर उन्होंने कृषि और किसानों पर अपनी राय रखी। उनका कहना था कि औद्योगिकीकरण के साथ ही कृषि को भी नजरंदाज नहीं करना चाहिए। कृषि की नींव पर ही आधुनिक भारत का भवन खड़ा किया जा सकेगा।

बाबा साहेब के अनुसार हर तरह के श्रमिकों – चाहे वे औद्योगिक हों या खेतिहर, उनको एक-सी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें मुआवज़ा और पेंशन शामिल हों। मोदी सरकार ने उनके सपनों को साकार करते हुए गरीबों के लिए कई योजनायें पेश की है जिसमें बीमा और पेंशन योजनायें भी शामिल हैं। बाबा साहेब का मानना था कि सभी ग्रामीणों को चाहे वे किसी भी जाति के हों, इस तरह जमीन बटाई पर देना चाहिए कि न तो कोई जमींदार हो, न कोई बटाईदार और न ही कोई श्रमिक। सामूहिक खेती होनी चाहिए। इससे सबमें खेती के प्रति अपनापन का भाव पैदा होगा। हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहेब श्रमिकों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध थे और उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना चाहते थे। मोदी सरकार के पिछले बजटों पर नजर डालने से ही प्रतीत हो जाता है कि प्रधानमंत्री उनके विचारों के भारत कि ओर कदम बढ़ा चुके हैं। ■

(लेखक भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

भारत ने ई-वीज़ा शक्ति का विस्तार किया

| प्रियदर्शी दत्ता |

देश में एक नई उदारवादी ई-वीज़ा व्यवस्था 1 अप्रैल, 2017 से लागू हुई है। यह दुनिया भर में भारत की यात्रा की योजना बना रहे 161 देशों के नागरिकों के लिए खुशियां लाएगी। इससे ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित अवधि तथा भारत में रहने की अवधि साथ-साथ ही बढ़ा दी गई है। हालांकि, भारतीय राजनयिक मिशनों द्वारा वीजा प्रदान करने की परंपरागत प्रक्रिया को बंद नहीं किया जाएगा।

वास्तव में ई-वीज़ा की प्रणाली पिछले सात वर्षों से शुरू हुई है। नव वर्ष दिवस 2010 पर भारत ने पांच देशों- जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लक्समबर्ग और न्यूजीलैंड के नागरिकों के लिए ही आगमन पर पर्यटक वीज़ा (टीवीओए) की शुरूआत की थी। एक साल बाद ही सरकार ने कंबोडिया, लाओस वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार और इंडोनेशिया के नागरिकों के लिए इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया।

केंद्र में सरकार के बदलने के बाद इस प्रणाली को काफी बढ़ावा मिला। भारत की यात्रा को एक सहज अनुभव बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार (ईटीए) से युक्त आगमन पर पर्यटक वीज़ा (टीवीओए) की सुविधा 27 सितंबर, 2014 को शुरू की गई। टीवीओएए-ईटीए आशय और क्षेत्र में अलग था। यह 9 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के माध्यम से भारत में प्रवेश के लिए 43 देशों के नागरिकों को ऑनलाइन पूर्व प्राधिकार था। इन देशों के नागरिक Https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html वेबसाइट पर वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं, उन्हें भारत आगमन पर वीजा सौंप दिया जाएगा। यह एक एकल प्रवेश वीजा है, जो 30 दिनों के लिए वैध होगा। हालांकि, टीवीओएए-ईटीए का नामकरण भी भ्रम से भरा था। अनेक पर्यटक यह मानते थे कि वीज़ा हवाई अड्डे पर उतरने पर दिया जाएगा। कुछ पर्यटक ऑनलाइन आवेदन किए बिना या स्थानीय भारतीय दूतावास से वीजा प्राप्त किए बिना ही यहां आए। इसलिए देश की नीति के अनुरूप एक नए नाम का गठन करने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है। Mygov.in पर इस नाम के बारे में एक प्रतियोगिता का आयोजन करके ई-टूरिस्ट वीजा को सबसे अच्छा विकल्प चुना गया। इस योजना को दोबारा ई-टूरिस्ट वीजा (ईटीवी) नाम दिया गया था, जो 15 अप्रैल, 2015 से प्रभावी हो गई। इस समय तक टीवीओए-ईटीए के तहत सरकार द्वारा पहले ही 1,10,000 (एक लाख दस हजार) वीजा जारी किए जा चुके थे। 2015 के अंत तक, कुल 113 देशों को इस योजना के दायरे के तहत लाया गया। अगस्त 2016 तक यह संख्या बढ़कर 150 हो गई थी।

डॉ महेश शर्मा, पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 6 फरवरी, 2017 को लोकसभा को सूचित किया कि वर्ष 2014, 2015 और 2016 के दौरान विभिन्न उद्देश्यों के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमशः 7.68 मिलियन, 8.03 मिलियन और 8.90 मिलियन (अनंतिम) रही है। इनमें से आगमन पर ई-वीजा वाले पर्यटकों की संख्या 2014, 2015 और 2016 में क्रमशः 0.39 लाख, 4.45 लाख और 10.80 लाख रही है। 149 देशों के पर्यटकों ने ई-वीज़ा सुविधा का लाभ उठाया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापार को आसान बनाने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के लिहाज से 30 नवंबर, 2016 को वीजा व्यवस्था उदार, सरल और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया। इसे अभी हाल ही में 1 अप्रैल से लागू किया गया है। अब ई-वीज़ा में पर्यटक, व्यापार, चिकित्सा और रोजगार श्रेणियां हैं। इंटर्न वीजा और फिल्म वीजा जैसी नई श्रेणियों को भी शामिल किया है।

विभिन्न देशों के क्रूज़ पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अब ई-वीजा सुविधा 24 हवाई अड्डों के साथ-साथ 3 बंदरगाहों (कोचीन, गोवा और मैंगलोर) के माध्यम से भारत प्रवेश के लिए 161 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। जल्दी ही मुंबई और चेन्नई बंदरगाहों को ई-वीज़ा सुविधा के तहत शामिल किया जाएगा। ई-वीज़ा योजना के तहत आवेदन की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। ताकि पर्यटक अपनी यात्रा की योजना को बेहतर ढंग से तैयार कर सके। ई-पर्यटक, ई-व्यापार वीजा पर दोहरे प्रवेश तथा ई-चिकित्सा वीजा पर तिहरे प्रवेश के साथ भारत में रूकने की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिनों तक कर दिया गया है। चिकित्सा पर्यटकों के लाभ के लिए ऐसे पर्यटकों की बड़ी संख्या में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे कुछ भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए अलग से आव्रजन काउंटर और सुविधा डेस्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

अब अधिकांश देशों के नागरिक पांच वर्ष की अवधि के लिए वह पर्यटन और व्यापार उद्देश्यों के लिए बहु प्रवेश वीजा प्राप्त कर सकते हैं। तत्काल जरूरत वाले मामलों में आवेदन के 48 घंटों के भीतर व्यापार और चिकित्सा वीज़ा प्रदान किए जा सकते हैं। बायोमेट्रिक नामांकन सुविधा वाले 94वीं भारतीय मिशनों ने 1 मार्च, 2017 से 5 साल के बहु प्रवेश वाले वीजा जारी करने शुरू कर दिए हैं। बाकी राजनयिक मिशनों में भी आने वाले समय में ऐसा कर दिया जाएगा।

यह लगता है कि एनडीए सरकार इस क्षेत्र में पिछली यूपीए -2 सरकार की तुलना में अधिक साहसिक कदम उठा रही है। 2014 से ई-वीजा का मुद्दा बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। नई वीजा व्यवस्था से भारत के एक अधिक अनुकूल पर्यटन स्थल बन जाने की संभावना है। इससे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम में सुविधा मिलेगी, जिसमें विदेशी निवेशकों की अनेकों बार भारत यात्रा करने की जरूरत पड़ती है। यह योजना डिजिटल इंडिया के विजन के भी समरूप है। इस कदम से राजनयिक मिशनों का मैन्युअल भार भी कम होने की संभावना है। मिशनों की वीजा खिड़कियां उन पर्यटकों के लिए खुली रहेंगी, जो ऑफ़लाइन की पद्धति से आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के विभिन्न देश ई-वीजा विकल्प के मार्ग को चुन रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत ने समय के अनुसार कदम उठाने का निर्णय लिया है। ■

नए वित्तीय वर्ष 2017 में जीएसटी की प्रभावी शुरुआत

विकाश आनन्द

पूरे देश को एकल कर प्रणाली के अंतर्गत लाने का जो विचार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लाया था, उसे वास्तविकता में तब्दील होने में एक दशक से अधिक समय लग गया। दअसल, अटलजी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति का गठन जीएसटी ढांचा तैयार करने के लिए किया था। अंततः नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जीएसटी को वास्तविकता में तब्दील किया। ऐतिहासिक जीएसटी अब 1 जुलाई से इस लक्ष्य को लागू करने के लिए निकटतम स्थिति तक पहुंच रही है।

जीएसटी विधेयक ने स्थानीय एवं राष्ट्रीय कर व्यवस्था को समान कर प्रणाली में बदलने का वादा पूरा किया और इस प्रकार देश के 29 राज्यों को एकीकृत किया। पहली बार संघ शासित क्षेत्रों और 1.3 अरब लोग कॉमन मार्केट में तब्दील हो गए। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आज तक का यह सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार करके दिखाया।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार बिलों को लोकसभा एवं राज्यसभा में 29 मार्च 2017 और 6 अप्रैल को पारित कर दिया गया। इन चार बिलों में एकीकृत जीएसटी, केन्द्रीय जीएसटी, केन्द्र शासित जीएसटी और माल एवं सेवा कर (राज्यों का प्रतिकर) हैं। जीएसटी कौंसिल जिनमें वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और राज्य वित्त मंत्रियों सदस्य हैं, जो अप्रैल 2017 के आखिर तक केन्द्रीय एक्साइज, सेवाकर और राज्य वैट तथा अनेक अन्य लेवियों के अलावा वर्तमान करों तथा अतिरिक्त प्रभारों को बदल देंगे। जीएसटी सम्बंधित पूरे कानून में संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम 2016 में जीएसटी कौंसिल शामिल है, जो कोआप्रेटिव फेडरेलिज्म का सही भाव है। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के शब्दों में कहा जाए तो 'यह पहली बार है जब केन्द्र और राज्य इकट्ठे हुए हैं और अपनी सम्पूर्ण प्रभुता को जीएसटी में मिलाकर वास्तविक रूप प्रदान किया है।' 29 मार्च को लोकसभा में श्री जेटली ने कहा था कि ''यह पहली बार है कि जब संवैधानिक स्वीकृति को फेडरल कंट्रेट में शामिल किया गया है। हम (संसद) कौंसिल को अपनी सिफारिशें कर सकते हैं, परन्तु साथ ही हमें इस फैडरल कंट्रेट का सम्मान करना

केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) के लागू करने के बिल का सारांश

केन्द्र राज्य की आंतरिक रूप से वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर सीजीएसटी लगा सकता है। इस आपूर्ति में बिक्री, ट्रांसफर और लीज को व्यापार बढ़ाने के लिए विचार किया जा सकता है।

कर-दरें: जीएसटी कौंसिल ने 5,12,18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरों की 'कर-संरचना' की सिफारिश की है। उच्चतम स्लैब में लक्जरी कारों, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तम्बाकू प्रोडक्ट्स, पान मसाला और कोयला शामिल रहेंगे ताकि पहले पांच वर्षों में संभावित राजस्व हानि से बचा जा सके।

सीजीएसटी से छूट: केन्द्र सूचना जारी कर जीएसटी के दायरे से कुछ वस्तुओं और सेवाओं को छूट दे सकती है। यह जीएसटी कौंसिल की सिफारिशों पर आधारित रहेगा।

जीएसटी के लाभ

जीएसटी कुशल कर व्यवस्था माना गया है और यह लागू एवं वितरणात्मक रूप में आकर्षक है। जीएसटी के लाभ इस प्रकार हैं:

- कर दरों में कमी करने और वर्गात्मक विवादों को समाप्त करने में आवश्यक है विस्तृत कर आधार
- बहुलवादी कर और उनके प्रभाव समाप्त करने के लिए
- कर संरचना का उदारीकरण और अनुपालन प्रक्रिया का सरलीकरण
- केन्द्र और राज्य कर प्रशासन की उदारीकरण, जिससे डुप्लीकेशन और अनुपालन लागत कम होगी।
- गलतियां कम करने और कुशलता बढ़ाने की प्रक्रिया के अनुपालन का ऑटोमेशन

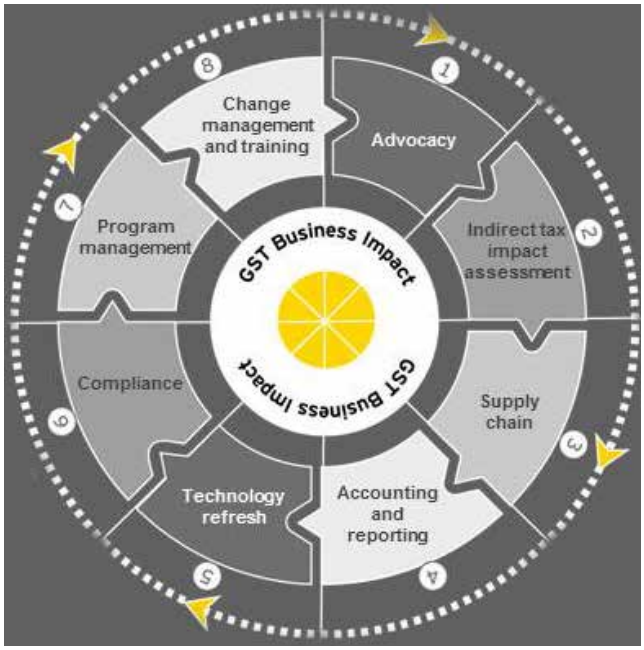

होगा, जिसमें राज्य और केन्द्र ने अपनी सम्प्रभुता को कौंसिल को दी है और इन बिलों के विभिन्न प्रावधानों को शामिल कर लिया है।'' हमारे प्रधानमंत्री ने इसे नए वर्ष, नए कानून, नए भारत की शुरूआत कहा है।

संविधान का 122वें संशोधन एक वाटरशेड के रूप में भारत के राजनैतिक-आर्थिक इतिहास पर गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि देश का आज तक का सबसे अधिक प्रगतिशील कर सुधार माना जा रहा है। जिससे हमारा जीवन और अधिक सरल बन जाएगा और उद्योग तथा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं और उपभोक्ता की सेवा की लागत कम हो जाएगी, जिसमें केन्द्र और राज्यों के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

विश्व बैंक में भारत का सरल रूप से 189 देशों में से 157वां स्थान है। जीएसटी से पहले नाफ्टा या यूरोपीय संघ अनेक करों के कारण वस्तु-सेवाएं महंगी और कठिन हो गई थीं। भारत की राज्य सीमाओं पर उसी तरह की लारियों की कतारों की स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बनी हुई हैं।

अर्थशास्त्रियों और टेक्नोक्रेटों ने जीएसटी का समर्थन बहुत पहले से किया था, जिसे वे वर्ष में 1-2 प्रतिशत प्वाइंट से आर्थिक आउटपुट को बढ़ावा देने वाला मानते हैं। प्रारम्भ में जीएसटी बिल का बहुत विरोध हुआ, परन्तु विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने क्षेत्रीय पार्टियों को समझाने में मदद कर विरोध को मिटा दिया।

2019 तक नए भारत के निर्माण के लिए अगला कदम जीएसटी बिल को पारित करना है जब भारत महात्मा गांधी की 150वीं जन्मदिन मना रहा होगा। गांधीजी ने सम्प्रभुता और मजबूत कोआप्रेटिव फ्रेडेलिज्म की सिफारिश की थी। वर्तमान जीएसटी का काम है कि इससे 3'सी कोआप्रेशन, कोआर्डिनेशन और केन्द्र-राज्यों के बीच कंवेंर्जेंस की स्थिति पैदा हो सके। एनडीए सरकार बिना किसी धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति के भेदभाव किए लोगों की बेहतरी के अपने वायदे निभाने का काम कर रही है। आने वाले वर्षों में जीएसटी के लाभों की सूची से भारत विकसित देशों की सूची में आ जाएगा, जिससे एकीकृत अप्रत्यक्ष करों और व्यापार करने की सुविधा पैदा हो जाएगी। ■

भारतीय जीएसटी सिस्टम की महत्वपूर्ण विशेषताएं

- मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किसी कर को जीएसटी कहा गया है।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या कॉमर्स के दौरान आपूर्ति के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल केन्द्रीय सरकार के पास ही रहेगी। राज्य सरकारें इंट्रा-स्टेट ट्रांजेक्शन, जिसमें सेवाएं भी शामिल होंगी, लागू कर सकेंगी।
- केन्द्र वस्तुओं और सेवाओं की इंट्रास्टेट आपूर्ति पर आईजीएसटी लगा सकेगा।
- सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडीशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडीशनल कस्टम ड्यूटी और विशेष एडीशनल ड्यूटी और स्टेट-लेवल कर, यथा वैट या बिक्री कर, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, क्रय कर, लक्जरी कर और ओक्ट्राय जीएसटी में निहित रहेगा।
- जीएसटी कौंसिल पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थों, यथा कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटरस्प्रिट, एविएशन टर्बाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस जैसे जीएसटी में शामिल रहेंगे- जीएसटी कौंसिल तारीख की सूचना प्रदान करेगी।
- पूरे भारत में प्रवेश कर/आक्ट्रोई को हटाने का प्रावधान करेगी।
- जीएसटी में फिल्मों, थियेटरों आदि पर राज्यों द्वारा लगाए गए मनोरंजन कर जीएसटी में निहित रहेंगे, परंतु पंचायतों, नगर निगमों या जिला स्तर पर कर जारी रहेंगे।
- समाचार पत्रों की बिक्री और विज्ञापनों पर जीएसटी लागू हो सकता है। इससे सरकार को पर्याप्त बढ़ा राजस्व प्राप्त हो सकेगा।
- राज्यों द्वारा विधि समझौतों पर लगाई गई स्टाम्प ड्यूटी जारी रहेगी।
- जीएसटी कौंसिल के प्रशासन की जिम्मेदारी उसी पर रहेगी, जो जीएसटी की उच्चतर पॉलिसी निर्माण की संस्था है। जीएसटी के सदस्यों के सदस्यों पर 'वित्त पोर्टफोलियों' के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य प्रभारी मंत्री शामिल रहते हैं।

देश के सभी वर्गों ने पार्टी में विश्वास जताया: नरेंद्र मोदी

6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। भाजपा स्थापना दिवस पर देशभर में हर वर्ष अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गत 6 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय गए। श्री मोदी और श्री शाह ने भारतीय जनता पार्टी के विचारक पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि देश के सभी वर्गों ने पार्टी में विश्वास जताया। प्रस्तुत हैं कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के संक्षिप्त समाचार–

उत्तर प्रदेश

भारतीय जनता पार्टी के 37वें स्थापना दिवस के मौके पर स्वच्छता के संदेश के साथ उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में झाड़ू लगाया।

प्रदेश प्रवक्ता डॉ. चन्द्रमोहन ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश मुख्यालय में झाड़ू थामी और स्वच्छ भारत का संदेश देते हुए कार्यालय परिसर साफ किया। प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यालय के सभी विभागों में स्वच्छता का जायजा लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी के मिशन स्वच्छ भारत को जन–जन तक पहुंचाने के ध्येय से भाजपा आगे बढ़ रही है। डॉ. चन्द्रमोहन ने बताया कि श्री मौर्य ने पार्टी के पदाधिकारियों से स्वच्छता मिशन को प्रभावी बनाने के लिए हर दृष्टिकोण पर चर्चा की। प्रदेश भर में सभी सेक्टर पर प्रभावी रूप से स्वच्छता, जीएसटी, भीम एप और केन्द्र की जन कल्याणकारी योजनाएं एवं प्रदेश की योगी सरकार के प्रथम कैबिनेट के किसान कर्जमाफी के ऐतिहासिक फैसले सहित सभी जानकारी जनता तक पहुंचेगी। स्वच्छता और मोदी सरकार की नीतियों से आमजन की समृद्धि तथा कैशलेस व्यवस्था से राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के अभियान में भाजपा आगे बढ़ेगी।

बिहार

भाजपा का 37वां स्थापना दिवस समारोह पूरे प्रदेश में मनाया गया। 63 हजार बूथों पर पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी जगहों पर पार्टी का झंडा लहराया गया। पार्टी ने बूथ अध्यक्षों के साथ पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। सुबह में पार्टी ने साइकिल मार्च निकालकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम पदार्थ बचाने के अभियान का प्रचार किया।

राजधानी पटना में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भी स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। पूर्व विधान पार्षद श्री हरेंद्र प्रताप ने कहा कि भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्री देवेश कुमार, विधान पार्षद श्री नवल किशोर यादव सहित कई वरिष्ठ नेतागण

उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़

भाजपा के 37वें स्थापना दिवस पर सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि मिशन 2018 के लिए अभी से जुट जाना है। भाजपा की सरकार बनानी है तो बूथ स्तर पर काम करना होगा।

प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री पवन साय ने कार्यकर्ताओं से संगठन को सशक्त बनाने का आह्वान किया। सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन को मंत्री सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत ने भी संबोधित किया। श्री अग्रवाल ने कहा कि केंद्र हो या राज्य, भाजपा की सरकार जनता की तकलीफों और सुविधाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाकर काम कर रही है। इन योजनाओं की कार्यकर्ताओं को जानकारी होनी चाहिए। श्री मूणत ने कहा कि पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बात सुनें।

राजस्थान

भारतीय जनता पार्टी के 37वें स्थापना दिवस पर भाजपा जयपुर शहर की ओर से कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लहराया। वे टोलियां बनाकर जुलूस के रूप मे वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे और पार्टी का झंडा लगाया।

भाजपा शहर अध्यक्ष श्री संजय जैन के नेतृत्व में पदाधिकारियों और

कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास और प्रदेशाध्यक्ष श्री अशोक परनामी के घर पर पार्टी का झंडा लहराया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी श्री मुकेश चेलावत सहित मोर्चों के शहर अध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

झारखंड

नगर विकास मंत्री श्री सी.पी. सिंह ने कहा कि भाजपा एक दिन में नहीं बढ़ी है। यह असंख्य कार्यकर्ताओं द्वारा लंबे समय तक किये गये संघर्ष का परिणाम है कि हम आज व्यापक रूप में खड़े हैं। संगठन के हमारे अभिभावकों ने सुदूर क्षेत्रों में चना, गुड़ व सत्तू खा कर कार्य किया, लेकिन किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। हमें इनकी विरासत को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए चिंता करने की जरूरत है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो जन आकांक्षाओं के साथ खरा उतरने के लिए काम करती है। श्री सिंह भाजपा रांची महानगर की ओर से प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गयी। पूर्व सांसद श्री यदुनाथ पांडेय ने कार्यकर्ताओं को जनसंघ काल से पार्टी की स्थापना व कार्यकर्ताओं के लंबे संघर्ष के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेवारी अब और बढ़ गयी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए काम करना है। महानगर अध्यक्ष श्री मनोज मिश्रा ने कहा कि पार्टी के नीति–सिद्धांतों पर चलते हुए कार्यकर्ता केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन–जन तक पहुंचायें।

हरियाणा

भाजपा के 37वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर वित्त मंत्री श्री अभिमन्यु और विधायक श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया। वित्त मंत्री ने स्थापना दिवस पर सभी को बधाई दी और कहा कि पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेने का दिन है। आज के दिन सभी महान नेताओं को स्मरण करते हैं, जिन्होंने जनसंघ के रूप में भारत की राजनीति में एक नई विचारधारा दी थी। पार्टी को विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी समेत सभी नेताओं ने योगदान दिया है और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। आज भाजपा की देश के साथ–साथ कई राज्यों में सत्ता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मंत्र अंत्योदय पर काम कर रही है।

श्री अभिमन्यु ने कहा कि भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो किसी परिवार की गुलामी नहीं करता। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं को बात रखने का अधिकार है। कार्यकर्ताओं की बात पर एक पद्धति के तहत पार्टी फैसले भी करती है।

हिमाचल प्रदेश

भारतीय जनता पार्टी के 37वें स्थापना दिवस पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और इतिहास से अवगत करवाया गया। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन्हें बताया गया।

इस अवसर पर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य किरण बावा ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा इतिहास से अवगत करवाया। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बूथ अध्यक्ष नरेश शर्मा ने अपना बूथ सबसे मजबूत के नारे को चरितार्थ करने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि हमारा बूथ मजबूत होगा तो हम हर चुनाव को आसानी से जीत सकते हैं।

उत्तराखंड

भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद सिंह रावत ने कहा कि भाजपा की यात्रा सिद्धान्तों और विचारों की यात्रा है। ये यात्र अभी अधूरी है। लक्ष्य सत्ता पाना नहीं है। हमें देश को सशक्त और समृद्ध बनाना है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक कारणों से लगे सभी मुकदमें वापस होंगे।

भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में सचिवालय के पास एक वैडिंग प्वॉइंट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री सीएम त्रिवेंद सिंह रावत ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विश्व पटल पर नई पहचान दी है। लक्ष्य हासिल करने को पार्टी आगे बढ़ रही है। सूबे में प्रचंड बहुमत मिला है और हमारी नीयत बिलकुल साफ है। हमने पहला प्रहार भ्रष्टाचार पर किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार चलाएंगे कि लोकायुक्त की जरूरत ही न पड़े। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन विकास प्रभावित नहीं होगा। ऑल वेदर रोड बनते ही विकास के रास्ते खुल जाएंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट, संगठन महामंत्री श्री संजय कुमार, विधायक श्री हरबंश कपूर सहित अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

पश्चिम बंगाल

प्रदेश भाजपा ने कोलकाता सहित राज्य भर में पार्टी का 37वां स्थापना दिवस मनाया। महानगर स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भी स्थापना दिवस मनाया गया। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री राहुल सिन्हा, पार्षद सुश्री मीना देवी पुरोहित, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजकमल पाठक सहित अन्य नेताओं ने मुरलीधर लेन स्थित प्रदेश मुख्यालय के निकट डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की मूर्ति पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री सिन्हा ने कहा कि बंगाल में भाजपा प्राकृतिक रूप से मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में तेजी से उभर रही है। राज्य में माकपा खत्म हो गई है, कांग्रेस अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है और तृणमूल अपनी विदाई के संकेत पाकर घबड़ाई हुई है। ममता सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। ■

दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी को बेनकाब करे: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 25 मार्च को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विशाल पंच परमेश्वर बूथ सम्मेलन को संबोधित किया और आम आदमी पार्टी की सरकार पर नई दिल्ली की अनदेखी को लेकर जम कर हमला बोला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का पर्दाफ़ाश करने की अपील की और एमसीडी चुनावों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का आह्वान किया।

श्री शाह ने कहा कि 2014 में जब लोक सभा चुनाव हुआ तो पूरे देश में एक अजीब प्रकार का माहौल था, सब ओर हताशा व निराशा का वातावरण था, युवा आक्रोशित थे, महिलायें असुरक्षा महसूस कर रही थी, देश की सरहदों की सुरक्षा भी अच्छी नहीं थी और उस वक्त देश की जनता ने श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को अपना नेता चुना और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक-के-बाद-एक कई काम हाथ में लिए, आज तीन साल बाद हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में आमूल-चूल परिवर्तन करने में सफल हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में एक भ्रष्टाचार-मुक्त, पारदर्शी एवं निर्णायक सरकार देने का काम किया है, इन तीन सालों में हमारे विरोधी भी मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज जब हम एमसीडी चुनाव में जा रहे हैं तो जहां एक ओर कांग्रेस है जिस पर 10 सालों के यूपीए सरकार के दौरान लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है तो वहीं दूसरी ओर अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में इतने अल्प समय में ही इतना भ्रष्टाचार किया, जितना किसी और ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल के खुद के सचिव को लेन-देन के में सीबीआई को अरेस्ट करना पड़ता है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने प्याज की खरीद में घोटाला किया, दिली की महिला आयुक्त की ऑफ़िस में भर्ती में घोटाला हुआ, सीएनजी की परमिट में घोटाला हुआ, पानी टैंकर का घोटाला हुआ, स्ट्रीट लाईट खरीदने में घोटाला हुआ और उनके एक मंत्री को तो जमीन खरीद के घोटाले में हवालात में बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इनके घोटालों की बहुत लंबी सूची है। दिल्ली शहरी स्लम विकास बोर्ड में भर्ती का घोटाला हुआ, वक्फ़ बोर्ड में करोड़ों रुपये का गलत तरीके से भुगतान हुआ, और सबसे बड़ा घोटाला तो यह हुआ कि दिल्ली के करदाताओं के पैसे को आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रसिद्धि के लिए पंजाब, गोवा, गुजरात आदि दूसरे राज्यों में एडवर्टाइज करके लुटाया जिसके लिए हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी को फटकार भी मिली। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के घोटालों को

दिल्ली के जन-जन तक पहुंचाने का काम करे और दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी को बेनकाब करे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाने की बात कही थी, एक भी नया स्कूल नहीं बना, 29000 प्राध्यापकों को नियुक्त करने की बात कही थी, कुछ नहीं हुआ, 30 नए डिग्री कॉलेज बनाने की बात की थी, एक की भी नींव नहीं रखी गई, तीन नए आईटीआई बनाने का वादा किया था, पांच नए पॉलिटेक्निक बनाने का वादा किया था, यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाया जाना था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अरविन्द केजरीवाल ने तो तीन पेज भर के वादे किये थे, तीन लाइन भी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने का वादा किया था, कुछ नहीं हुआ। अस्पतालों में 30 हजार बेड लगाने थे, कुछ नहीं हुआ, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की सेवाओं को अपग्रेड करना था, कुछ नहीं हुआ। 60 करोड़ रुपये का आवंटन करके आम आदमी कैंटीन बनाने की बात कही गई थी पर दिल्ली वालों को कहीं पर भी कैंटीन नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि दो लाख पब्लिक टॉयलेट बनाने का वादा किया गया था लेकिन केजरीवाल जी, दो लाख तो छोड़ दीजिये, आप 2000 का भी हिसाब दे दीजिये तो भी दिल्ली की जनता को लगेगा कि कुछ तो हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अस्थाई कर्मचारियों को परमानेंट करने का वादा आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ फिर भी केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली से किये हुए जिन-जिन वादों को पूरा नहीं किया है, उसे लेकर कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के पास जाएं और आम आदमी पार्टी सरकार की असलियत से जनता को रूबरू कराएं।

श्री शाह ने कहा कि जब-जब चुनावों का मौसम आता है, तब-तब केजरीवाल जी वादों की झड़ी लगाते हैं, फिर से चुनाव का मौसम आ गया है, अब फिर से वे जनता से झूठे वादे करने वाले हैं लेकिन चुनाव के बाद जब दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को खोजती है तो कभी वे पंजाब में मिलते हैं, कभी गोवा में मिलते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं तो कभी यूपी में मिलते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी जहां-जहां गए, वहां-वहां उन्होंने हारने का रिकॉर्ड बनाया चाहे वह लोक सभा का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो या फिर गोवा का। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने साफ़-सुथरा शासन देने की बात कही थी, कहा था, क़ानून-व्यवस्था ठीक करेंगे, केजरीवाल जी, क़ानून-व्यवस्था तो छोड़ो, आप यदि अपने विधायकों को ही संभाल कर रखें तो भी दिल्ली की जनता पर बहुत मेहरबानी हो जायेगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी के पूर्व क़ानून मंत्री फर्जी डिग्री के आरोप में धरे जाते हैं, महिला कल्याण मंत्री रेप के आरोप में पकड़े जाते हैं और उनके प्रवक्ता आशुतोष जी उनकी तुलना गांधी जी से करते हैं, खाद्य मंत्री रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद एक-के-बाद-एक केजरीवाल जी के 13 विधायकों पर क्रिमिनल केस हुए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने की बात करते थे, शुचिता लाने की बात करते थे, क्रिमिनलाइजेशन ख़त्म करने की बात करते थे लेकिन आज उनके विधायक एक-के-बाद-एक क्रिमिनल केस में फंसते जा रहे हैं फिर भी केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी, यदि आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो एमसीडी के चुनाव में प्रचार करने के पहले इन 13 विधायकों पर दिल्ली की जनता को जवाब दीजिये, यदि आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो आप अपने भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच कराने की घोषणा कीजिये लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे।

श्री शाह ने कहा कि एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राज्य की जनता के घर-घर संकल्प करके जाएं और एमसीडी चुनाव जीत कर आएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एमसीडी का चुनाव केवल एमसीडी जीतने भर का चुनाव नहीं है, बल्कि अगली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को उखाड़ कर फेंक देने के लिए नींव डालने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विकास का एक यज्ञ चल रहा है, बहुत जरूरी है कि विकास का यह यज्ञ दिल्ली में भी चले और यह तभी हो सकता है जब दिल्ली में एक अच्छी सरकार और अच्छी एमसीडी हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार हो, एक ऐसी एमसीडी हो जो केंद्र सरकार के साथ राजनीतिक कारणों से झगड़ा न करें, बल्कि केंद्र से सहयोग करके दिल्ली का विकास करे। उन्होंने कहा कि जन संघ के समय से ही यदि सबसे पहले हमने कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीता तो वह दिल्ली का म्युनिसिपिल कॉरपोरेशन जीता था, इस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी तीनों कॉरपोरेशन में जीत का परचम लहरायें, इसका संकल्प लेकर कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के घर-घर जाएं। ■

आज जब हम एमसीडी चुनाव में जा रहे हैं, तो जहां एक ओर कांग्रेस है जिस पर 10 सालों के यूपीए सरकार के दौरान लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है तो वहीं दूसरी ओर अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में इतने अल्प समय में ही इतना भ्रष्टाचार किया, जितना किसी और ने नहीं किया।

दीन दयाल अंत्योदय योजना— राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

आजीविका पर विशेष जोर के जरिए जीवन में ला रहा है बदलाव

पं. दीन दयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) 3.6 करोड़ से भी अधिक परिवारों के जीवन और आजीविका में अहम बदलाव ला रहा है। यही नहीं, इन परिवारों की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल हो गई हैं। एसएचजीए ग्राम संगठनों (वीओ) और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के अंतर्गत महिलाओं की सामूहिक संस्थाओं ने परिवर्तनकारी सामाजिक प्रधानता विकसित की है, जिससे महिला-पुरुष संबंधों में बदलाव आ रहा है, सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है और ग्राम सभाओं एवं पंचायती राज संस्थानों में उनकी भागीदारी संभव हो पा रही है। इस कार्यक्रम से महिलाओं का विश्वास बढ़ा है जिसके फलस्वरूप वे आजीविका में विविधीकरण के लिए एक निरंतर समुदाय संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) के नेतृत्व में मार्गदर्शन के जरिए कौशल एवं सक्षमताओं का विकास करने के बाद आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक से ऋण पाने का प्रयास करने लगी हैं। 1.50 लाख महिला समुदाय संसाधन व्यक्ति (सीआरपी), जो खुद गरीबी के दायरे से बाहर आ गई हैं, आज सतत कृषि को बढ़ावा देनेए बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने और पशुओं की देखभाल के लिए पैरा वेट्स का एक कैडर विकसित करने में परिवर्तन के महान कारकों (एजेंट) के रूप में उभर कर सामने आ चुकी हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये महिला सीआरपी गांवों में सामाजिक बदलाव लाने में भी अहम भूमिका अदा करने लगी हैं।

वर्ष 2011 में इस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक एसएचजी की महिला सदस्यों ने बैंक ऋण के रूप में 1.06 लाख करोड़ रुपये की राशि तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर ली है। वर्ष 2014-15 में 20,000 करोड़ रुपये के बैंक लिंकेज रहे, जबकि वर्ष 2015-16 में एसएचजी ने ऋण के रूप में 30,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि प्राप्त की। फरवरी 2017 तक 29,000 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि का वितरण हो चुका है और वित्त वर्ष 2016-17 में लगभग 35,000 करोड़ रुपये से लेकर 38,000 करोड़ रुपये तक की राशि ऋण के रूप में जुटाये जाने का अनुमान है। वर्ष 2016-17 में बैंक लिंकेज के विश्लेषण से अनेक राज्यों जैसे कि असम, बिहार, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में क्रेडिट लिंकेज में उल्लेखनीय वृद्धि होने की जानकारी मिली है। यही नहीं, देश भर में बैंक लिंकेज का प्रसार हुआ है क्योंकि एसएचजी अनेक उत्तरी राज्यों में भी गरीबों के जीवंत एवं मजबूत संस्थानों के रूप में उभर कर सामने आये हैं। एसएचजी देश के दक्षिणी राज्यों में पहले से ही मजबूत एवं जीवंत रहे हैं।

दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत टिकाऊ कृषि के तौर-तरीकों को बढ़ावा देने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के अंतर्गत 30 लाख से भी अधिक महिला किसानों को सहायता सुलभ कराई गई है।

दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) कार्यक्रम देश की लगभग एक तिहाई ग्राम पंचायतों में अपनी पहुंच सुनिश्चित कर चुका है और इसके साथ ही इस कार्यक्रम के समेकन एवं विस्तारीकरण के लिए भी निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। ■

डिजिटल भुगतान पर 14 लाख उपभोक्ताओं और 77,000 व्यापारियों को मिले 226 करोड़ रुपये के पुरस्कार

भारत को कैश-लेस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिजिटल भुगतान को लेकर चलाई गई मुहिम अब एक जन आंदोलन का हिस्सा बनती जा रही है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की दो योजनाओं को लोगों से भारी समर्थन मिल रहा है। 25 दिसंबर 2016 को डिजिटल पेमेंट्स के लिए दो प्रोत्साहन योजनाएं लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना शुरू की गई थीं। इन योजनाओं के शुरू होने के बाद से 14 लाख लोगों और 77,000 व्यापारियों को प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार धन राशि मिली है।

दोनों प्रोत्साहन योजनाओं के तहत अब तक कुल 226,45,40,000 रुपए (इसमें 176,95,00,000 रुपये ग्राहकों को, जबकि 49,50,00,000 रुपये व्यापारियों को) मिले हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने वालों में सभी विभिन्न आयु वर्ग, लिंग और आर्थिक स्तर के लोग शामिल हैं। बिहार में आजमगढ़ गांव के 27 वर्षीय मकैनिक देविंदर ने लकी ग्राहक योजना के तहत एक लाख रुपये जीते हैं। 12 के एक परिवार में छह भाइयों के बीच सबसे बड़े होने के नाते उन्होंने काफी लेनदेन की। अब उनका मानना है कि डिजिटल भुगतान करना बहुत आसान है। इससे पहले वह लेनदेन के लिए भाई के बैंक खाते का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वह जल्द ही अपना बैंक खाता खोलेंगे।

नीति आयोग ने प्रोत्साहित करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को लेकर 25 दिसंबर 2016 को ग्राहकों के लिए लकी ग्राहक योजना (एलजीवाई) और व्यापारियों के लिए डिजिधन व्यापार योजना (डीवीवाई) की शुरुआत की थी। यह दोनों योजनाएं 14 अप्रैल 2017 तक जारी रहेंगी। इन योजनाओं के जरिये रोजाना 15,000 विजेता बन रहे हैं, जो कुल पुरस्कार राशि के रूप में 1.5 करोड़ रुपये उन्हें हर दिन मिल रहे हैं। इसके अलावा, इसके तहत 14,000 साप्ताहिक विजेता बन रहे हैं जो प्रत्येक सप्ताह 8.3 करोड़ रुपये जीत रहे हैं। ग्राहक और व्यापारी रुपे कार्ड, भीम या यूपीआई (भारत इंटरफेस फॉर मनी या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस),यूएसएसडी आधारित *99# सेवा एवं आधार सक्षम भुगतान सेवा (एईपीएस) के जरिये रोजाना और साप्ताहिक लकी ड्रा पुरस्कार जीत सकते हैं। ■

एक साल में रेल यात्रियों की संख्या 7 करोड़ बढ़ी

भारतीय रेलवे में लोगों की यात्रा को बेहतर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का असर अब दिखने लगा है। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के मुकाबले 2016-17 में भारतीय रेलवे में यात्रा करने वालों की संख्या 7 करोड़ अधिक रही है। गौरतलब है कि 5 साल में पहली बार रेलवे में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रेलवे के मुताबिक हाल में उठाए कदमों के चलते यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

दरअसल रेल मंत्रालय के सतत प्रयासों के चलते रेलवे उस क्रम को तोड़ने में सफल रहा जो 2012 से बना हुआ था। 2016-17 में यात्री संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। रेलवे ने 2016-17 वित्त वर्ष में और अधिक यात्रियों को सुविधा देने के लिए अनेक कदम उठाए, जिनमें 87 नई ट्रेन सेवाएं शुरू की गई। इसके साथ ही अनेक रेल सेवाओं का विस्तार किया गया है और फेरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। नियमित ट्रेनों में 586 अतिरिक्त कोच जोड़े गए, जिससे 31 मार्च 2017 तक 43,420 नयी बर्थ सृजित हुईं।

एक अन्य खबर के अनुसार, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करवाने पर अब 30 जून तक सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने डिजिटल मोड से पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग को सर्विस चार्ज से मुक्त कर दिया था। यह योजना नोटंबदी के बाद 23 नवंबर, 2016 को शुरू गई थी। पहले यह छूट 31 मार्च, 2013 तक देने का ऐलान किया गया था। अब यह अवधि बढ़ाकर 30 जून, 2017 तक कर दी गई है। ■

उत्तर प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला

किसानों के 36,000 करोड़ रुपये के फसली ऋण माफ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 4 अप्रैल को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में 31 मार्च, 2016 तक लघु व सीमान्त किसानों को जितना भी फसली ऋण दिया गया है, उसका 31 मार्च, 2017 को अचुकता अवशेष माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। फसली ऋण माफी की अधिकतम सीमा प्रति किसान एक लाख रुपए होगी। इसके अलावा, एन0पी0ए0 ऋणों को एकमुश्त समाधान (ओ0टी0एस0) के तहत राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से राइट ऑफ़ किया जाएगा, जिस पर अनुमानित वित्तीय भार लगभग 6000 करोड़ रुपए होगा। इस पूरी योजना में 86 लाख से अधिक लघु व सीमान्त किसानों को लाभ होगा, जिन्होंने बैंकों से फसली ऋण ले रखा है।

योजना की कुल लागत लगभग 36 हजार करोड़ रुपए होगी, जिसमें एकमुश्त समाधान योजना की लागत लगभग 6000 करोड़ रुपए होगी। एकमुश्त समाधान योजना से ऐसे लगभग 7 लाख किसान पुनः बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे, जिन्हें ऋणग्रस्तता के कारण बैंकों ने फसली ऋण देना बन्द कर दिया था। प्रदेश के एक हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ तक के सभी किसान सीमान्त किसान की श्रेणी में आएंगे। इस प्रकार 2 हेक्टेयर अर्थात् 5 एकड़ तक के सभी किसान लघु किसान की श्रेणी में आएंगे। योजना का लाभ प्रदेश के सभी लघु व सीमान्त कृषकों को मिलेगा। प्रारम्भिक गणना के अनुसार प्रदेश में ऐसे कुल 86.68 लाख लघु व सीमान्त किसान हैं, जिन्होंने बैंकों से फसली ऋण लिया हुआ है।

फसली ऋण माफी योजना हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 8 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, संस्थागत वित्त/कृषि/सहकारिता व राज्य बैंक समन्वयक सदस्य हैं। यह समिति सभी पहलुओं का अध्ययन कर विस्तृत फसली ऋण माफी योजना तैयार करेगी व उसका मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर क्रियान्वयन करेगी। साथ ही, समिति योजना के वित्त पोषण हेतु भी अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर सरकार द्वारा इस हेतु वित्तीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। क्रियान्वयन के अतिरिक्त समिति की इस योजना के सतत् अनुश्रवण में भी सक्रिय भूमिका होगी। प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र के अनुसार मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में लघु एवं सीमान्त किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के क्रम में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश की लगभग 78 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें 68 प्रतिशत परिवार कृषि पर निर्भर हैं। किसानों की संख्या का लगभग 93 प्रतिशत लघु व सीमान्त किसान हैं। इसी से स्पष्ट है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था लघु व सीमान्त

किसानों पर काफी हद तक निर्भर है। गत तीन वर्षों में सूखा, बाढ़ व ओलावृष्टि का सर्वाधिक कुठाराघात लघु व सीमान्त किसानों पर हुआ है, जिससे वे फसली ऋण की अदायगी भी नहीं कर पा रहे हैं तथा उनकी सूदखोरों व साहूकारों के ऋण के भंवरजाल में फंसने की प्रबल आशंका है। इससे कृषि सेक्टर व प्रदेश के विकास की गति भी अवरुद्ध होने की सम्भावना है।

2016-17 में जहां राज्य के सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत अनुमानित है, वहीं कृषि एवं पशुपालन सेक्टर में यह 5.3 प्रतिशत ही रहने का अनुमान है। 2011-12 से 2014-15 के मध्य जहां प्रदेश में प्रति व्यक्ति कुल आय में 3.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर रही, वहीं कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में यह वृद्धि मात्र 1.2 प्रतिशत रही। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि पिछले तीन वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के दंश को झेल रहे इन सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण माफ किए जाएं।

इसी आशय से लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से उद्घोषित अपनी प्रतिबद्धता 'कृषि विकास का बने आधार' के क्रियान्वयन का राज्य सरकार द्वारा अपनी पहली मंत्रिमण्डलीय बैठक में निर्णय लिया गया। इससे लघु एवं सीमान्त किसानों को इस हेतु सक्षम बनाया जाएगा कि वे बैंकिंग व्यवस्था का लाभ लेकर कृषि में निवेश करें, ताकि वे न केवल स्वयं स्वावलम्बी हों, अपितु राज्य के कृषि सेक्टर के उत्पादन व उत्पादकता में भी वृद्धि हो। ■

101 नई एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी

भारत विश्व में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बावजूद यहां केवल 2.2 प्रतिशत फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण ही किया जाता है। भारत में प्रत्येक खाद्य उत्पादन केंद्र पर सस्ते शीत भंडार और शीत श्रृंखलाओं की आवश्यकता है। मौजूदा शीत भंडार सुविधा कुछ राज्यों में ही केंद्रित है और मौटे तौर पर 80 से 90% शीत भंडारों का आलू के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। भारत को इस बारे में लंबा रास्ता तय करना है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय देश में राष्ट्रीय कोल्ड चेन ग्रिड का निर्माण कर रहा है, ताकि सभी खाद्य उत्पादक केन्द्रों को शीत भंडारण और प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ा जा सके।

मंत्रालय द्वारा 27 मार्च को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नई कोल्ड चेन अवसंरचना को स्थापित करने में जुटा हुआ है, जिसमें शीत भंडारण और प्रसंस्करण दोनों ही सुविधाएं शामिल हैं। मंत्रालय ने मई, 2015 में 30 कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। आज मंत्रालय ने पूरे देश में फैली 101 नई एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं फलों और सब्जियां, डेयरी, मछली, मांस, समुद्री उत्पाद, मुर्गी उत्पाद, खाने के लिए तैयार/पकाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के लिए हैं।

मंत्रालय रणनीतिक योजना द्वारा कोल्ड चेन अवसंरचना की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे पूरे देश में कोल्ड चेन ग्रिड बनेगा। इससे माननीय प्रधान मंत्री के किसानों की आय को दोगुना करने के मिशन को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे कृषि आपूर्ति श्रृंखला में बर्बादी कम हो जाएगी और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर जुटाने में भी मदद मिलेगी।

इन एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं से संबंधित राज्यों में न केवल खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को भी उनके उत्पाद की बेहतर कीमत उपलब्ध होगी जो किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में एक कदम होगा।

कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना में उद्यमियों को

10 करोड़ तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इन नई एकीकृत कोल्ड चेन परियोजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा सृजन के लिए 3100 करोड़ रुपये के कुल निवेश की जरूरत पड़ेगी। इन परियोजनाओं के लिए कुल अनुमानित ग्रांड-इन-एड 838 करोड़ रूपये होगी।

इन 101 नई कोल्ड चेन परियोजना से 2.76 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज / नियंत्रित वायुमंडल / फ्रोजन भंडारों की अतिरिक्त क्षमता, 115 मीट्रिक टन प्रति घंटे की व्यक्तिगत त्वरित फ्रीजिंग (आईक्यूएफ) क्षमता, 56 लाख लीटर प्रति दिन दूध प्रोसेसिंग की क्षमता, 210 मीट्रिक टन प्रति बैच ब्लास्ट फ्रीजिंग और 629 रेफ्रिजेरेटेड/ इंसुलेटेड वाहनों की क्षमता उपलब्ध होगी।

इन एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं से संबंधित राज्यों में न केवल खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को भी उनके उत्पाद की बेहतर कीमत उपलब्ध होगी जो किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में एक कदम होगा। बुनियादी ढांचे से जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की बर्बादी घटाने में मदद मिलेगी इसके अलावा कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन में सहायता मिलने के अलावा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।

उपरोक्त कोल्ड चेन अवसंरचना और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और देश में आवश्यक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना बुनियादी ढांचे का और विस्तार करने तथा मजबूती प्रदान करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना होगा। इससे उत्पादकों से प्रसंस्करणकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों से छोटी, सुसंगत और संपीड़ित आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिलेगी और इससे फल और सब्जी तथा दुग्ध प्रसंस्करण तथा गैर-बागवानी खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। ■

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता					
	एक वर्ष	₹350/- ☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/- ☐
	तीन वर्ष	₹1000/- ☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/- ☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

कोबा, गांधीनगर (गुजरात) स्थित भाजपा कार्यालय 'कमलम' में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, मंचासीन हैं गुजरात प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेतागण

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने कमल संदेश के आजीवन सदस्य

कमल संदेश की कैशलेस सदस्यता लें!

आह्वान

आपको जानकर हर्ष होगा कि 6 दिसम्बर 2016 को पार्टी मुख्यालय में भाजपा 'कमल संदेश' का आजीवन सदस्य बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. **श्री अमित शाह** ने पत्रिका की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि 'कमल संदेश' भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय पत्रिका है और यह पाक्षिक रूप में हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है।

हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं 5000/– रुपए का चैक देकर 'कमल संदेश' की आजीवन सदस्यता ली। साथ ही केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर सहित अनेक केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आजीवन सदस्यता ग्रहण की गई है।

'कमल संदेश' हिन्दी एवं अंग्रेजी के दोनों अंकों को 5000/– (पांच हजार रुपये) की सदस्यता शुल्क देकर नियमित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब 'कमल संदेश' के लिए कैशलेस भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध है। कृपया 5000/– (पांच हजार) रुपये का योगदान कर आप भी 'कमल संदेश' (हिन्दी+अंग्रेजी) का आजीवन सदस्य बनें।

एक साल (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹350/-	**तीन साल** (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹1000/-
आजीवन (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹3000/-	**आजीवन** (हिन्दी+अंग्रेजी)	—	₹5000/-

'कमल संदेश' के हमारे पाठकों से अनुरोध है कि इसकी सदस्यता लेकर जीवंत वैचारिक आंदोलन के भागीदार बनें।

कैशलेस बना 'कमल संदेश' सदस्य बनें और बनाएं

☞ **www.kamalsandesh.org, www.bjp.org** पर जाकर कैशलेस भुगतान क्रेडिट/डेबिट/नेटबैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।

☞ साथ ही दिए बार कोड से मोबाइल द्वारा सीधा भुगतान भी कर सकते हैं।

chillr
ACCEPTED HERE
Scan the QR code to make a payment
Click on SCAN & PAY and enter amount
Add this contact to pay
+91 9911026172

"**कमल संदेश**" के नाम से कृपया चेक/ड्राफ्ट निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:
कमल संदेश, पीपी–66, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली– 110003